

वर्ष 9	अंक 1	विषय सूची	कार्तिक – 2064	वि .	नवम्बर	2007२३
२३		सरदार पटेल और पंथ निरपेक्षता	–गौरीशंकर भारद्वाज			2
		पीड़ा	–पं. जगदीश लाल शर्मा			4
		तिब्बत के दलाई लामा				6
		कठघरे में वाममोर्चा				7
		पं. बंगाल के गाँवों में गरीबी कम !				7
		फासीवाद का नया ठिकाना				8
		भूमिहीन ग्रामीणों की बढ़ती मुश्किलें				9
		मुसलमानों की समस्याएं जानने के लिए एक और सर्वे				10
		हिन्दुओं की पहचान नष्ट करने का जेहाद				11
		वेबसाइट के जरिए युवाओं तक पहुँचा हाईटेक अल कायदा				11
		शहरों का रुख करने वाले नक्सली हाईटेक हुए				12
		जेहादी व सिख आतंकवादियों की करतूत				12
		गोकशी में लिप्त तीन को गांव से निकाला				13
		धार्मिक यात्रा की आड़ में दवाओं का कारोबार				13
		दारुल उलूम में विदेशियों का बार-बार आना ठीक नहीं				14
		बंदों की बंदगी में फरक न हो				14
		कानून, समाज और साहित्य	– पवन चौधरी 'मनमौजी'			15
		कविताएं, पुस्तक समीक्षा, पाठकों के पत्र,				17–20
		'गुजरात का सच' के संबंध में विहिप द्वारा दिया गया संयुक्त प्रेस-वक्तव्य				21
		Seven facts that nail the lies about Gujarat - B.P.Singhal				22
		Duty does not permit repentance -				
		-The butchers of Calcutta	-Andrew Whitehead			24
		Am I a Hindu?	- Chandan Mitra			26
		The dragon still looms	-Udayan Namboodiri			28
		Pakistani First Law & Labour Minister,				
		J.N.Mandal's Resignation Letter				30
		Diary of Events, Select Articles and Book Reviews				38-47

पंथनिरपेक्षता के प्रहरी

सरदार पटेल और पंथ निरपेक्षता

गौरीशंकर भारद्वाज

सरदार पटेल की पंथनिरपेक्षता की अवधारणा व्यावहारिक थी। वह सभी संप्रदायों के व्यक्तियों को समान न्याय प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। किन्तु उनकी पंथनिरपेक्षता का सबसे बड़ा आधार राष्ट्रीयता व देशभक्ति के विचार व भाव थे। श्री वी.शंकर ने ठीक ही लिखा है **"Sardar Patel's deluted secularism was more popular and had more adherents than Pt. Nehru's absolute secularism."** अतः आज भी सरदार पटेल की पंथनिरपेक्षता की अवधारणा प्रासंगिक हैं। सरदार पटेल संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। उनके द्वारा दिनांक 26 मई 1949 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत अल्पसंख्यकों संबंधी रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों, कल्याण व विकास के लिए उनके मन में पूरा आदर और संकल्प था किन्तु साथ ही उनका यह दृढ़ मत था कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ हिन्दुत्व का परित्याग अथवा हिन्दुओं के हितों की सर्वथा उपेक्षा नहीं है। यह तो अन्य संप्रदायों के प्रति न्यायोचित दृष्टिकोण रखना है। उनकी पंथ निरपेक्षता की सबसे बड़ी कसौटी थी— देश के प्रति वफादारी और अटूट देशभक्ति। इस रिपोर्ट में निहित निम्नलिखित अंश विशेष उल्लेखनीय हैं।

क. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जैसे कुछ प्रगतिशील राष्ट्रीय मानस वाले नेताओं का अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने में प्रस्ताव से मतभेद था, जो आरंभ से ही किसी भी प्रकार के आरक्षण के विरुद्ध थे। मेरा विश्वास है कि आज उनको यह देखकर खुशी हो रही होगी कि उनकी अभिलाषा पूरी हो रही है।

ख. जिन लोगों का यह दावा था कि इस देश में दो राष्ट्र हों और दोनों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती तथा जिन लोगों का अभी भी विचार है कि उनके पास एक ऐसा वतन होना चाहिए जहाँ वे आजादी से साँस ले सकें, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि वे पाकिस्तान जाकर उस स्वतंत्रता का उपयोग करें और हमें शांति से रहने के लिए छोड़ दें। जो लोग मजहब के आधार पर प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं, उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं है।

ग. कोई जाति वर्ग यह सोचे कि उसके हित देश के हितों से भिन्न हैं तो यह उनकी एक बड़ी भारी भूल है।

घ. वस्तुतः किसी भी अल्पमत का भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि वह बहुमत में विश्वास रखे।

सरदार पटेल पंथनिरपेक्षता में विश्वास रखते हुए भी एक अत्यंत धर्मप्राण व निष्ठावान् हिन्दू थे। वह हिन्दू संस्कृति के कट्टर समर्थक थे। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण उन्हीं के सद्प्रयासों का सुपरिणाम है। पं. नेहरू के प्रबल विरोध करने के बावजूद सरदार पटेल के आग्रह पर प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। सरदार पटेल के दीर्घ अवधि तक अत्यंत विश्वासपात्र व अन्तरंग निजी सचिव रहे श्री वी. शंकर ने अपनी फस्तक "My Reminiscences of Sardar Patel" में लिखा है कि सरदार पटेल हिन्दू समाज के फनरुत्थान और फनर्जागरण में विश्वास रखते थे। उन्होंने सदा यह अनुभव किया कि हिन्दू कुल मिलाकर विनीत स्वभाव के और समझौता करने वाले हैं। हिन्दू देश में बहुमत में हैं किन्तु उनका पिछड़ापन और उनमें संगठन व अनुशासन की कमी एवं दूसरे संप्रदायों के शरारती तत्त्वों से अपनी रक्षा करने में उनकी असमर्थता, उनके चरित्र की दुर्बलता है।

दिसम्बर 1947 से जनवरी 1948 के संकटपूर्ण काल में लखनऊ में दिए गए भाषणों में उन्होंने कुछ मुसलमानों की देश के प्रति वफादारी की कमी तथा घोर सांप्रदायिक दृष्टिकोण की कटु आलोचना की थी। इससे पं. नेहरू ने त्यागपत्र की धमकी दी थी और गाँधी जी से शिकायत की थी कि देश में सांप्रदायिक समस्या को लेकर सरदार पटेल का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वास्तव में मुसलमानों की स्थिति को लेकर सरदार पटेल के विचारों को इन भाषणों के सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया, जिसके लिए उनकी उस समय अनुचित आलोचना की गई।

देश के विभाजन के समय दिल्ली में उग्र सांप्रदायिक तनाव के दौरान सरदार पटेल ने वास्तविक पंथनिरपेक्षता तथा मानवीय संवेदना का उच्च स्तरीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में शरण लेने वाले हजारों

मुसलमानों की सैकड़ों सशस्त्र लोगों द्वारा घेराबन्दी किए जाने की सूचना मिलने पर सरदार पटेल ने तत्काल स्वयं अपनी उपस्थिति में सेना की सहायता से सभी मुसलमानों को सुरक्षित निकाला।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मुसलमानों की देश के प्रति संदेहपूर्ण वफदारी तथा अराष्ट्रीय गतिविधियों के विषय में 17.10.1947 को लिखे पत्र के उत्तर में सरदार पटेल ने 18.7.1948 को उनको भेजे गए पत्र में लिखा कि मुसलमानों के बारे में भरत में कुछ अराजक तत्वों की उपस्थिति में निहित संभावनाओं के बारे में मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। हम राष्ट्र की सुरक्षा की आवश्यकताओं और पंथ निरपेक्षताओं के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। (Selected Correspondence of Sardar Patel)

दिनांक 9.10.1950 को हैदराबाद में गाँधी भवन के शिलान्यास के अवसर पर सरदार पटेल ने स्पष्ट कहा था कि :

पमैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि वे भारतीय नागरिक के रूप में समान अधिकार रखते हैं तथा वे भी शांति, कानून तथा सरकार के पूर्ण संरक्षण में रहने के हकदार हैं। साथ ही प्रत्येक नागरिक को चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार करना होगा, अनुभव करना होगा और काम करना होगा। कुछ मुसलमान सोचते हैं कि पाकिस्तान उनके लिए तीर्थ स्थल है। यदि वे हृदय से ऐसा सोचते हैं तो उनका कर्तव्य है कि वे अविलम्ब भारत छोड़ कर पाकिस्तान में जा बसैं। (My Reminiscences of Sardar Patel- V.Shankar यदि सरदार पटेल की चेतावनी को ओर ध्यान दिया गया होता ते आज हैदराबाद – आतंक, अराजकता व देशद्रोह का केन्द्र नहीं बनता।

काश्मीर को लेकर सरदार पटेल ने मुसलमानों से कहा था कि पमैं भारतीय मुसलमानों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में आपने काश्मीर के मामले पर अपना मुँह क्यों नहीं खोला था? आपने पाकिस्तान के काश्मीर पर आक्रमण की निन्दा क्यों नहीं की? ये बातें लोगों के दिमाग में शक पैदा करती हैं। मैं मुसलमानों का दोस्त होने के नाते स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अब आपका कर्तव्य है कि आप देश की मुख्यधारा में अपने आपको आत्मसात कर लें। मैं आपसे बिना लागलपेट के स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप दो घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी आँखों में धूल झाँके। जो अभी भी दो घोड़ों पर सवार हैं, उन्हें हिन्दुस्तान छोड़ना होगा। (My Reminiscences of Sardar Patel- V.Shankar) सच तो यह है कि आज तक किसी अखिल भारतीय स्तर के मुस्लिम नेता या इमाम अथवा मुस्लिम बुद्धिजीवी ने खुलकर भारत में काश्मीर के विलय का सार्वजनिक समर्थन नहीं किया।

सरदार पटेल ने मार्च 1950 को पं. नेहरू को लिखे पत्र में कहा था कि पमैंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि हमारे पंथ निरपेक्षता के आदर्श भारत के हमारे मुस्लिम नागरिकों पर भी जिम्मेदारी डालते हैं। भारत की आबादी के बहुत बड़े भाग के लोगों में मुसलमानों की देश के प्रति वफदारी के विषय में बने रहने वाली शंकाओं और भय को दूर करने की जिम्मेदारी मुसलमानों की है। इन शंकाओं और भय का आधार है – कुछ मुसलमानों की दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रवृत्तियाँ। (Selected correspondence of Sardar Patel)

वास्तव में पं. नेहरू का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण का रहा। किसी पीड़ित या उपेक्षित मुसलमान के मामले में पं. नेहरू बहुत ध्यान देते थे किन्तु किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति के विषय में वह ऐसा नहीं करते थे। एक कांग्रेसी नेता होने के नाते उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के प्रति उनकी विशेष जिम्मेदारी है किन्तु जिस बात पर उनका ध्यान कभी नहीं गया, जैसा कि एक भूपू. राज्यपाल ने कहा था कि यदि अल्पसंख्यकों की मांगों को पूरा करते रहे तो एक दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जब बहुसंख्यक की रक्षा करनी पड़ जाएगी। सरदार पटेल – पं. नेहरू के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे कि केवल मुसलमानों की सुरक्षा और उनका हितवर्धन किया जाए तथा हिन्दुओं की सुरक्षा व हितों की उपेक्षा की जाए।

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक पंथनिरपेक्षता की निम्नलिखित दो समानान्तर धाराएँ प्रवाहमान रही हैं।

क. पटेलवादी पंथनिरपेक्षता की अवधारणा – जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सभी को समान रूप से न्याय एवं किसी भी संप्रदाय का तुष्टीकरण नहीं बल्कि सभी संप्रदायों को पूर्ण सम्मान पर आधारित है।

ख. नेहरूवादी पंथनिरपेक्षता की अवधारणा – जो पं. जवाहर लाल नेहरू और उनकी खानदानी कांग्रेस पार्टी द्वारा पोषित एवं अपने राजनीतिक स्वार्थसाधन हेतु वोटों के सौदागर सपा, बसपा, राजद व डीएम.के. आदि राजनीतिक दलों एवं

तथाकथित मानवाधिकारवादियों द्वारा समर्थित घोर अन्ध हिन्दुत्व विरोधी तथा अल्पसंख्यकों के निर्लज्ज तुष्टीकरण पर आधारित है।

यह कैसी नेहरूवादी पंथनिरपेक्षता है कि गुजरात में प्रतिक्रिया स्वरूप हुए दंगों पर तो रातदिन विलाप किया जाता है लेकिन काश्मीर में हुए भयंकर नरसंहार, हिन्दू मंदिरों का ध्वंस एवं काश्मीरी पंडितों का बलात् घाटी से पलायन के फलस्वरूप बेघरबार होने पर धृतराष्ट्र की संतति के इन अन्धे-बहरे व उद्भ्रान्त छद्म पंथनिरपेक्षतावादियों के कान पर जूँ नहीं रेंगती। वास्तव में सरदार पटेल प्रसूत पंथनिरपेक्षता को अपनाने से ही राष्ट्र का कल्याण, भावनात्मक ऐक्य और सर्वतोमुखी विकास होगा।

15 दिसम्बर, 1950 को यह भारत-प्रदीप सदा के लिए बुझ गया।

भारत-रत्न उस महान् कर्मयोगी को शत-शत नमन।

पूर्व विधायक, दिल्ली

पीड़ा

आक्रान्ताओं ने पीड़ा दी। अपनों ने सांप्रदायिक व कट्टर, रूढ़िवादी, धर्मान्ध, न जाने क्या-क्या लांछन लगाकर हिन्दू समाज को पीड़ित किया। परिणामस्वरूप हिन्दू समाज सक्षम, समर्थ, मंचाधीश होने पर भी अपने आपको उभार नहीं पाया। दूसरी तरफ कर्मकाण्ड की जटिलताओं के कारण हिन्दू समाज रूठता, छूटता, टूटता गया। सुविधाजीवी, पराधीन होकर आंतरिक मतान्तरण करने लगा। इधर धर्म गुरुओं में भी गुरु परम्परा पनपी। अलग-अलग झण्डे व डण्डे लेकर विभिन्न देवी-देवताओं आदि के चमत्कारपूर्ण कृतियों का वर्णन करते हुए नए-नए मतों का उभार हुआ। हिन्दू समाज भ्रमित हो गया। ज्योतिषी समाज ने कर्मकाण्ड को एवं ज्योतिष ज्ञान को साधक से ज्यादा बाधक बना दिया। यथा जन्मकुण्डली में मांगलिक योग नहीं, दोष बना दिया, जिससे वैवाहिक संबंधों में विलम्ब होने लगा। तनावग्रस्त हिन्दू समाज भ्रम व भटकाव की स्थिति में पहुँच गया। इतिहास विकृतिकरण के कारण हिन्दू देवी देवताओं का चरित्र-चित्रण अभद्र एवं कलंकित स्थिति में पेश होता गया। व्यवसायियों ने अपने पैकिंग सामग्री कलेण्डरों के ऊपर देवी-देवताओं का चित्रण किया जो कूड़ेदानों में डलने लगे। गऊ माता दूध देने के पश्चात् सड़ा-गला खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दी गई। माँ अपमानित, तो हम कैसे होंगे सम्मानित? हिन्दू पर्वों-त्यौहारों में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी त्यौहार में किन्तु परन्तु लगता गया। जोशीले भाषण दिए गए, धर्मशास्त्रों से भाषण दिए गए किन्तु किसी ने भी इनमें एकरूपता लाने का प्रयास नहीं किया जबकि यह अतिसरल कार्य है।

भगवान् श्रीराम से जुड़े हुए समस्त पर्व अयोध्या से, श्रीकृष्ण से जुड़े हुए पर्व मथुरा-वृन्दावन से, भगवान् शिव के पर्व काशी से, भगवान् गणपति के महाराष्ट्र से हैं। इसी प्रकार समस्त प्रान्तों के कुछ पर्व लेकर पूरे देश में एक मान्य बिन्दु के आधार पर पंचांग की सहायता से मनाएं तो सामाजिक-धार्मिक एकता लाई जा सकती है। दुर्भाग्य से एक आवाज़ उठने लगी है कि उस वक्त ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्म, मंत्र-तंत्र, मुहूर्त, चमत्कार, देवी-देवता कहाँ थे जब हमारे देश की बहु-बेटियां माताएं लूट का माल घोषित करके आक्रान्ताओं एवं मतान्तरित अपनों के द्वारा ही यौन शोषित उत्पीड़ित होकर कराह रही थीं। 15 आक्रान्ताओं ने विशाल नालान्दा विश्वविद्यालय नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। पानीपत के मैदान में 15 हजार मराठों पर 1500 आक्रान्ता हावी हुए। हम गुलाम हुए, इतिहास साक्षी है। ठीक है धर्मशास्त्र मूल्यावान हैं लेकिन समस्त-जन धर्मशास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते। इसलिए परम्परानुसार चलते हैं जो परिवार से परिवार में आगे बढ़ती जाती है।

एक सोच मंच से यह भी उभर कर पाई कि हमारे देश में लाखों की संख्या में धर्माचार्य जगद्गुरु, कथावाचक, प्रवचनकर्ता, संत, महामण्डलेश्वर, देश के चारों कोनों में धर्म की अलख जगाए हुए हैं। देश में 26 लाख से ज्यादा धर्मस्थानों में धर्मरक्षक साधक के रूप में व्यवस्था समितियों के पदाधिकारी ब्राह्मण फजारीगण भी मौजूद हैं। एक-एक धर्माचार्य अपने 10-10 अनुयायियों को भी लेकर एकमंचीय होकर उद्घोष करने की स्थिति में उभरें तो सरकारें क्या संसार भी इन्हें मान्य करेगा। उसे प्रचार से जरूर बचना होगा जो सड़कों पर और मीडिया द्वारा प्रचारित-प्रसारित किया जाता है कि हिन्दुओं के पास मंदिर मुद्दे के अलावा कुछ नहीं? जगतवासियों से जुड़ा हुआ सन्त मानव जीवन के लक्ष्य स्वस्थ सुखी जीवन की ओर मानव समाज को अग्रसर करता है। गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, कानून, व्यवस्था, देश में बढ़ती अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता देश में व्याप्त कलूषण-प्रदूषण,

जल-संसाधनों का अभाव, कृषि पर छाया संकट, बढ़ती आत्महत्याएं, दान आधारित मंदिरों, धर्मस्थानों की बढ़ती संख्या तथा उनमें घटती श्रद्धालुओं की संख्या, मंदिरों का प्रसाद बनना लेकिन उनसे प्रसाद गायब होना। धर्मस्थानों का स्वावलम्बी न होना। हिन्दुओं के गोविन्द, गीता, गाय, गंगा, गायत्री -पांचों गकारों एवं श्रीराम सहित अन्य देवी-देवताओं का लांछित चरित्र-चित्रण, मंदिरों में चढ़े फूलों का निस्तारण न होना, बढ़ता आतंकवाद आदि के कारण भयभीत हिन्दू को इन समस्याओं से कैसे मुक्त किया जा सकता है? यह ठीक है कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं लेकिन राजधर्म पालन करने वाले नेताओं का उपर्युक्त की ओर ध्यान आकर्षित करना अपना फर्ज मानते हैं। अभी भी वक्त है कि संतजन कृपया अपनी श्रेष्ठता-विशिष्टता के अहम् को एक बार भौतिक सुविधाओं से उबर कर एकमंचीय होकर जनमानस को निर्देश दें-साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, आपस में हम नहीं लड़ेंगे।

यदि ये रामसेतु अथवा रामजन्मभूमि अथवा उपर्युक्त वर्णित अन्य समस्याएं लेकर जनमानस के सामने प्रकट होंगे तो सरकार को त्वरित निर्णय लेना ही पड़ेगा। जितना देश इन राजनीतिबाजों का है उतना ही धर्माचार्यों एवं अन्य सभी का है। कथावाचकों का, प्रवचनकर्ताओं का विशेष उत्तरदायित्व है कि कथाओं में पीड़ाहरण-पीड़ाभरण करते हुए गौरवशाली इतिहास का वर्णन करते हुए जनमानस के सामने निर्भय-निष्कपट होकर प्रस्तुत करें-जीयें आन से और मरें मान से, कर्मपथ पर मुस्कुराते हुए चले शान से।

श्रीमद्भवद्गीता का यह संदेश जीवनी शक्ति का कारक-धारक है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जब भी समाज पर संकट आया है तो संत-धर्माचार्य समाज-निर्भीक होकर अग्रणी हुआ है। जैसे भगवान् श्रीरामचन्द्र जी ने निशिचरहीन करों महि भुज उठाइ पण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन्ही जाइ जाइ सुखदीन। आसुरीवृत्तियों के विनाश का संकल्प भगवान् श्रीराम ने किसी राजनीतिक मंच पर नहीं अपितु शिक्षा ज्ञान के भण्डार आश्रमों में जाकर संत जनों की प्रेरणा से किया था।

भय लगे जब सपनों से तो क्या करें, खतरा हो जब अपनों से तो क्या करें? शरण ले निःसंकोच तब किसी सिद्ध संत की, सन्मार्ग पर चलना सिखाए, दे दिशा भगवंत की। संत समाज किसी राजनीतिक दल विशेष से जुड़ाव नहीं रखता अपितु समाज अथवा राष्ट्रहित में निर्णय लेता है। आज नितांत आवश्यकता है कि संत समाज सामूहिक रूप से अविलम्ब निर्णय करे अन्यथा श्री रामधारीसिंह दिनकर की पंक्तियां भुलाने से भी नहीं भूल पाएंगी :

वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है।

बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है।

क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही कड़ी हो।

हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।

विनीत :

पं. जगदीश लाल शर्मा

बी-48, रघुवीर एन्क्लेव, नज़फगढ़, दिल्ली

तिब्बत के दलाई लामा

अमेरिका जब दलाई लामा को कांग्रेसनल गोल्ड मैडल के जरिए अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजता है तो इसके विरोध में चीन का गुस्सा कितना बONA और पिलपिला नजर आता है। वह चाहकर भी अगर अमेरिका का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो उसका कारण साफ है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका विश्व में अकेली ऐसी महाशक्ति है जिसको किसी भी हद तक जाकर दादागीरी दिखाने से कोई परहेज नहीं और अपनी तमाम शक्ति गाथाओं के बावजूद चीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बल्कि इसलिए भी कि तिब्बत पर अपना अवैध कब्जा जमा लेने के करीब आधी सदी के बीत जाने के बावजूद चीन उसे अपने एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्से के रूप में न तो दुनिया के सामने पेश कर सकता है और न ही दुनिया से वैसा मनवा सका है। आज से करीब छह दशक पहले जब पंडित नेहरु तिब्बत को चीन के हवाले करने के राजनीतिक और सांस्कृतिक अपराध कर आए थे, उस अपराध बोध से भारत आज तक उबर नहीं पाया है तो चीन, जिसे अपराध का सौ फीसदी फायदा मिला, उस अपराध बोध से भला कैसे उबर सकता है। वह नहीं उबर सकता है, इसका सबसे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए कि चीन द्वारा कब्जाए जाने के बाद दमन और धौंसपट्टी का शिकार बना दिए गए तिब्बत के निर्वासित, सैन्य शक्तिविहीन और महज आध्यात्मिक गुरु होने के बावजूद अकेले दलाई लामा चीन की पूरी ताकत और तानाशाही पर भारी पड़ते रहे हैं। तिब्बती तो तिब्बती ही हैं, वे चीनियों की तरह हान नहीं। इसलिए तो चीन ने करोड़ों हान तिब्बत में बसा कर वहाँ की आबादी और आबादी में रची-बसी तिब्बती संस्कृति का चेहरा और संतुलन बिगाड़ कर रख देने की भरसक कोशिश कर ली है। पर इससे न तो वह तिब्बतियों द्वारा वहाँ चलाए जा रहे संघर्ष को खत्म कर पाया और न ही दुनिया से तिब्बत नामक मुद्दे का वजन और चमक कम कर पाया है, और न ही दलाई लामा के आध्यात्मिक बल से उपजी राजनीतिक हस्ती को खरोँच लगा पाया है। चीनी नेताओं के मन में बसे डर की हालत तो यह है कि दलाई लामा कहते हैं, क्योंकि वे इससे अधिक दबाव बना पाने की हालत में ही नहीं हैं कि उन्हें स्वतंत्रता नहीं, सिर्फ चीन में रहते हुए अर्थपूर्ण स्वायत्तता चाहिए, पर चीनी सत्ताधीशों के कान इतना तक सुनने को भी तैयार नहीं हैं। दलाई लामा भरोसा दिलाते रहते हैं कि इस स्वायत्तता को वे आजादी की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे पर चीनी सत्ता केन्द्रों में पसरा अपराध बोध एक संत की वाणी का भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। चीन के हाथों तिब्बत का खुला निर्मम दमन उस दुनिया में हो रहा है जहाँ कहने को एक राष्ट्र संघ है, लोकतंत्र का दम भरने वाले असंख्य देश हैं और मानव अधिकारों का नाम लेकर छत पर से चिल्लाने वाले ढेरों संगठन मौजूद हैं। चिंता तो बस इतनी है कि तब इस कुटिल दुनिया में तिब्बत की कौन सुनेगा जब दलाई लामा भी नहीं रहेंगे। न जाने चीन कब कौन सा खेल खेल दे क्योंकि उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी अड़चन है, उसका नाम है दलाई लामा।

‘राष्ट्रीय सहारा’ दिल्ली दि. 20 अक्टूबर 2007 से साभार

कठघरे में वाममोर्चा

प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को यह लोकतांत्रिक हक हासिल है कि वह भारत-अमेरिका परमाणु मुद्दे के मौजूदा हथकड़ी के संदर्भ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर फब्तियां कसे। भाजपा की फब्तियों का जवाब कांग्रेस और प्रधानमंत्री को देना है पर देश के जिम्मेदार नागरिकों का यह सोचने का पूरा अधिकार बनता है कि आखिर क्यों भारत जैसी उदीयमान आर्थिक व राजनीतिक महाशक्ति के वर्तमान प्रधानमंत्री दुनिया के सामने एक कमजोर नेता के रूप में पेश कर दिए गए हैं? भारत जैसे बड़े और ऐतिहासिक देश का प्रधानमंत्री, वयस्क वोट आधारित 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले लोकतंत्री देश भारत का प्रधानमंत्री, नेहरू और इंदिरा जैसे तेजस्वी प्रधानमंत्रियों की विरासत को थामने वाले शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री क्यों अपने हाथ मलता हुआ नजर आ रहा है? अगर आज दुनिया के सामने भारत का प्रधानमंत्री एक विवश और किंकर्तव्यविमूढ़ नेता जैसा नजर आ रहा है कि तो निःसंदेह भारत की तस्वीर को बिगाड़ने वाली इस हालत का ठीकरा वाममोर्चा के ऊपर डाले बिना नहीं रखा जा सकता जिसने देश की लोकतंत्री प्रणाली के तमाम फायदे उठाने की चतुराई दिखाते हुए इस प्रणाली की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रखा है। अगर आपने केन्द्र में एक गठबन्धन सरकार को एक साझा कार्यक्रम के आधार पर बाहर से समर्थन देने का बीड़ा उठाया था और कैबिनेट में शामिल होकर जवाबदेही का बोझ ढोए बिना वह बीड़ा उठाया था तो आपसे यह अपेक्षा कतई नहीं है कि आप अपनी विचारधाराई जिदों को शीर्ष पर रखकर सरकार को लड़खड़ा दें। आपको भारत-अमेरिका परमाणु करार स्वीकार नहीं तो वापस लीजिए समर्थन और जाइए जनता के सामने। ये तो कोई बात न हुई कि आप समर्थन भी वापस न लेंगे और सरकार को भी नहीं चलने देंगे, उसे लूला-लंगड़ा बनाकर रख देंगे। कभी आप इस करार को क्रियान्वित न करने की जिद करते हैं तो कभी आप परमाणु एजेंसी से संवाद तक स्थापित न करने की हिदायतें दे डालते हैं। आपको इतना सुनना तक भी मंजूर नहीं कि अमेरिका आपकी सभी कोशिशों को मानो फुस्स करते हुए कहता है कि करार को पूरा करने की कोई लगी-बंधी समय सीमा नहीं है। आखिर आप चाहते क्या हैं? अगर अमेरिका का अंधा विरोध ही आपकी विचारधारा है तो उसे छाती से चिपका कर आप एक से दूसरे पेड़ पर छलांगते रहिए। पर प्रधानमंत्री, सरकार और देश को बंधुआ बनाकर दुनिया की निगाह में उसे अविश्वसनीय और हास्यास्पद बनाकर रख देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उतनी ही हैरानी कांग्रेस पर भी हो रही है कि वह किस बड़े लक्ष्य की उम्मीद में इतनी जलालत भोगने को भी मजबूर बनी हुई है? कूदिए मध्यावधि चुनाव में और ले आइए जनादेश। एक निस्तेज और ढुलमुल सरकार से आखिर किसका भला हो रहा है? जितना लंबा जीवन इस लुंज-फंज बना दी गई सरकार को मिलेगा, देश और कांग्रेस को उतना ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। यह एक ऐसा राजनीतिक गणित है जिसको समझने में दूसरा कोई भी गलती कर सकता है किन्तु सोनिया गांधी नहीं।

'राष्ट्रीय सहारा' दिल्ली दिनांक 19.10.2007 से साभार

प. बंगाल के गाँवों में गरीबी कम !

विरोध की राजनीति के आदी हो चुके कामरेडों को पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होना भी हजम नहीं हो रहा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा है और गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित करने की मांग की है। विधानसभा से पारित प्रस्ताव को लेकर मंत्रियों का एक दल दिल्ली आया था।

गत मार्च में योजना आयोग ने वर्ष 2004-05 की गणना पर आधारित देश में गरीबी के आँकड़े जारी किए। 1999-2000 की गणना के बाद योजना आयोग ने 2004-05 में गरीबों की गणना की थी।

नए आँकड़ों के मुताबिक पूरे देश में गरीबी घटी है। इसमें पश्चिम बंगाल भी है। यहां शहरों में गरीबी बढ़ी है लेकिन गांवों में गरीबी घटी है। आँकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल का प्रतिशत 24.7 हो गया है और यह आबादी दो करोड़ से अधिक है।

शहरों में गरीबी का प्रतिशत 14.80 है और आबादी 35.14 लाख है जबकि गांवों में गरीबी का प्रतिशत 28.6 है और आबादी 173.22 लाख है। राज्यों में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय पिछली गणना के 350.17 रुपये के मुकाबले 382.82 रुपये हो गई है और शहरों में 409.22 के मुकाबले 449.32 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई है। यह प्रतिशत काफी है। **दूसरे कुछ राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति आय कम है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी अधिक है।** लेकिन देश के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में गरीबी कुछ घटी है।

फिलहाल माजरा यह है कि पश्चिम बंगाल में ग्रामीण गरीबों की आबादी घटना कामरेडों को हजम नहीं हुआ। उसे आँकड़ा पच नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल की वाम गठबंधन सरकार का कहना है कि उसके यहाँ ग्रामीण गरीब अधिक हैं।

पश्चिम बंगाल की विधानसभा में इसी साल एक अगस्त को नियम 185 के तहत सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की गिनती का तरीका ही गलत है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र में जितने गरीब रहते हैं उतने मार्च 2007 की गणना से मेल नहीं खाते। यानि राज्य में वास्तव में जिनते लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं उनकी उतनी संख्या गणना में दिखाई नहीं गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पारित किए गए इस प्रस्ताव को लेकर मंत्रियों का एक दल दिल्ली आया। उसने ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को अपना ज्ञापन सौंपा और साथ ही विधानसभा से पारित किया गया प्रस्ताव भी। बाद में इन नेताओं ने प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया।

‘राष्ट्रीय सहारा’ दिल्ली दिनांक 16.10.2007 से साभार

फासीवाद का नया ठिकाना

नंदीग्राम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यवाही को लोकतंत्र पर धब्बा बता रहे हैं संदीप पांडे

मैं फरवरी 2007 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित की जाने वाली हरिफर बिजली परियोजना के विरोध में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए कोलकाता गया था। सिंगुर व नंदीग्राम की भांति हरिफर में भी स्थानीय नागरिक प्रस्तावित परियोजना का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इससे स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर संकट की आशंका थी। बैठक में प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बोलने वालों में लेखिका महाश्वेता देवी और संस्कृतिकर्मी सांवली मित्र भी थीं। सांवली मित्र ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को फासीवादी बताया। वामपंथी तो फासीवाद के कट्टर दुश्मन माने जाते रहे हैं इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार के लिए फासीवादी शब्द में सत्तारूढ़ माकपा की प्रशासन में पकड़ को देखकर मैं अचंभित रह गया। पश्चिम बंगाल से लौट कर मुझे ऐसा लगने लगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भले ही ठीक नहीं हो, किन्तु राजनीतिक असहमति तथा विरोध दर्ज कराने की गुंजाइश ज्यादा है, जो लोकतंत्र के अस्तित्व की प्राथमिक शर्त है। 14 मार्च 2007 को फलिस और माकपा कार्यकर्ताओं ने जन विरोध को हिंसा से कुचलने की कोशिश की। लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य किए गए। पिछले दिनों तो माकपा कार्यकर्ताओं ने बर्बरता की हदें पार कर दीं। हाल ही में अस्तित्व में आई हरमद वाहिनी ने नंदीग्राम पर सशस्त्र हमला बोलकर इलाके पर कब्जा जमा लिया। इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं ने फलिस को भी साथ लेने की जरूरत महसूस नहीं की। कबीलाई अंदाज में उन्होंने अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति से जुड़े लोगों के घर जलाए गए। मारपीट, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं हुईं। विचित्र है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का यह कथन कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मार्च में अपने गांवों से खदेड़ दिए गए थे। वे घर लौटने को उतावले थे। उन्होंने यह भी कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया।

फलिस प्रशासन को नाकाम कर गुंडों-अपराधियों की मदद से माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा नंदीग्राम पर कब्जा करने को नैतिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक, संवैधानिक या किसी भी तरीके से कैसे जायज ठहराया जा सकता है? क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य की भाषा 2002 में गोधरा की दुर्घटना के उपरांत गुजरात की हिंसा को जायज ठहराने के लिए नरेन्द्र मोदी के इस कथन के समान नहीं है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। नंदीग्राम में जो हुआ वह अक्षम्य है। मात्र तीन-चार सौ लोगों को बसाने के लिए दस से बारह हजार लोगों के घर जलवा दिए गए। करीब डेढ़ हजार परिवार राहत शिविर में

शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को यह बताना होगा कि नंदीग्राम में आखिर किस ईंट का जवाब किस पत्थर से दिया गया है? लोग घरों में लौट रहे हैं तो उनसे वसूली की जा रही है, घरों पर माकपा का झंडा फहराने को कहा जा रहा है। माकपा की शर्त न मानने का नतीजा होता है तबाही। खेत में खड़ी फसल को जबरदस्ती काट लेने की धमकी दी जा रही है। फलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी ने पहले मार्च में और अब नवम्बर में भी नंदीग्राम में माकपा कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर सार्वजनिक चिंता व्यक्त की तो वरिष्ठ माकपा नेताओं ने उनका मखौल उड़ाया। प्रदेश माकपा सचिव बिमान बोस ने तो उच्च न्यायालय को भी नहीं बख्शा। 14 मार्च की घटना पर उसके पैफसले को सरकार के कामकाज में दखलंदाजी बताया।

इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू करने के बाद से सत्ता में इतना अहंकार नहीं देखा गया। इसलिए 14 नवम्बर 2007 को कोलकाता में बिना किसी बैनर के हजारों बुद्धिजीवी, कलाकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता नंदीग्राम की दुर्घटना पर अपना रोष प्रकट करने के लिए सड़क पर उतर आए। यह पश्चिम बंगाल के इतिहास में इस तरह का अनोखा व सबसे बड़ा प्रदर्शन था। माकपा अब बुद्धिजीवियों को भी सावधान रहने की धमकी दे रही है। सारे लक्षण हैं कि माकपा फासीवाद की सोच से ग्रस्त हो चुकी है। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य कहते हैं कि वह सरकार के मुखिया होने से पहले माकपा के नेता हैं तो वह उन कल्याण सिंह की याद दिला देते हैं जिन्होंने विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद कहा था किउनकी पहली निष्ठा आरएसएस के प्रति है। कल्याण सिंह सरकार को तो तत्कालीन केन्द्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, किन्तु बुद्धदेव भट्टाचार्य के मामले में कांग्रेस की नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस और माकपा के बीच एक गठबंधन बन चुका है, जिसमें कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वह नंदीग्राम पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। नंदीग्राम में नवम्बर की हिंसा के तुरंत बाद वाम मोर्चे ने केन्द्र सरकार को नाभिकीय समझौते को साकार करने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से वार्ता करने की हरी झण्डी दे दी है।

नंदीग्राम की घटना जितनी जनविरोधी है उतना ही जनविरोधी है भारत-अमेरिका नाभिकीय समझौता। इस तरह कांग्रेस और माकपा, दोनों ही अपने-अपने हित साध रहे हैं। नंदीग्राम में महिलाओं के अपमान का विशेष जिक्र करना जरूरी है। यदि गुजरात में गर्भवती महिलाओं के साथ बर्बरता की घटनाएं हुई थीं तो बंगाल में माकपा कार्यकर्ताओं ने भी यही किया। पश्चिम बंगाल में न सिर्फ एक संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है, बल्कि एक राजनीतिक संकट भी है। नंदीग्राम में जिस तरह की करतूत माकपा कार्यकर्ताओं ने की है उससे साफ हो गया है कि दक्षिण से लेकर वामपंथ तक के सभी राजनीतिक दलों का चरित्र एक जैसा ही है। यदि देश के सभी राजनीतिक दल अलोकतांत्रिक, जनविरोधी और यहां तक कि फासीवादी हो जाएंगे तो इस लोकतंत्र में जनता के लिए क्या विकल्प बचेगा?

;लेखक मैग्सेसे फरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता हैंद्व

'दैनिक जागरण' दिल्ली दि. 30.11.07 से साभार

ग्राम विकास

मुस्लिम तुष्टिकरण

भूमिहीन ग्रामीणों की बढ़ती मुश्किलें

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार आजादी के आन्दोलन का प्रथम चरण राजनीतिक-संवैधानिक स्वायत्तता हासिल करके जनतंत्र की स्थापना करना था। खेत जोतने वाले को जमीन का मालिकाना हक देना, समय स्वाधीनता का दूसरा महत्वपूर्ण चरण था। पर अफसोस कि आजादी के 60 साल बाद भी करोड़ों लोग भूमिहीन हैं। विश्वबैंक के अनुसार भारत में करीब 17 करोड़ लोग पूर्णतः भूमिहीन हैं तथा 25 करोड़ लोगों के पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। सन् 1975, 1996 व 1999 में बनाए गए तमाम भू अधिकार संबंधी कानून मजाक बन कर रह गए हैं।

हकीकत यह है कि महज 20 फीसदी भूमि पर ही हदबंदी कानून व 6 फीसदी भूमि पर काश्तकारी कानून लागू किया जा सका है। भूमि हदबंदी के तहत 76 फीसदी भूमि वितरित ही नहीं हुई है। भूदान आन्दोलन में विनोबा भावे के साथी बाल विजय भाई का कहना है कि वैश्वीकरण के दौर में भूमिहीन ग्रामीणों व विस्थापित आदिवासियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सरकारी नीतियां ऐसे लोगों के पक्ष में कहीं खड़ी नजर नहीं आतीं। आजादी के छह

दशकों में विकास के लिए जो भूमि अधिग्रहीत की गई, उसका खामियाजा 4 करोड़ लोग विस्थापित जीवन के रूप में भुगत रहे हैं। भू-सुधार कानूनों के तमाम छिद्रों, राजनीतिक प्रतिबद्धता में कमी, प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार व सामंती मानसिकता के चलते भू-वंचितों और खेतिहर मजदूरों के सामने विकट समस्या पैदा हो गई है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि आजाद भारत में तथाकथित भूमि सुधार के 272 कानून और 13 संवैधानिक संशोधनों के बाद भी अधिकांश वंचितों को भू-अधिकार नहीं मिला। दबंग लोगों व प्रशासन की मिलीभगत के कारण गरीब आज भी अपनी जमीन पर मजूरी ही करने को अभिशप्त हैं।

भूमिहीनों के लिए बीते दो दशकों से संघर्ष करने वाले व एकता परिषद के अध्यक्ष पीवी राजगोपाल का मानना है कि बदलते वक्त की मांग है कि देश के लिए नई दृष्टि के साथ भूमि सुधार के एजंडे पर फिर से विचार-विमर्श किया जाए।

‘राष्ट्रीय सहारा’ दिल्ली दिनांक 22.10.07 से साभार

मुसलमानों की समस्याएं जानने के लिए एक और सर्वे

मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा अब गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी मिलेगा। सरकार ने सच्चर समिति के बाद अब देश भर के मुस्लिम बहुल 90 जिलों में इस समुदाय की क्षेत्रवार समस्याओं का अध्ययन करने का जिम्मा आईसीएसएसआर ;इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च को सौंपा है। इन इलाकों में मुसलमानों के कल्याण के लिए दी जाने वाली योजनाओं/सहायता में वहां के गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सच्चर समिति द्वारा मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों का आकलन करने के बाद अब सरकार ने रिपोर्ट में सुझाए गए मुस्लिम बहुल 90 जिलों में मुसलमानों की जमीनी हकीकत का नए सिरे से पता लगाने के लिए आईसीएसएसआर को लगाया है।

दरअसल देश भर में फैले मुसलमानों की शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में तो स्थिति लगभग एक जैसी ही है पर आमतौर पर मुसलमानों की क्षेत्रवार समस्याएं अलग-अलग हैं। सरकार ने इसी के मद्देनजर प्रत्येक मुस्लिम बहुल जिले में उनकी समस्या विशेष का पता लगाने और उसके निदान के लिए रास्ता सुझाने के लिए नयी पहल की है।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि दरअसल सच्चर समिति ने वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक उन 90 जिलों का चयन किया है, जिनमें मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है। उक्त रिपोर्ट में मुसलमानों की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन तो किया गया है, पर क्षेत्रवार उनकी छोटी-बड़ी समस्याओं पर कोई विशेष अध्ययन नहीं हुआ था।

सरकार ने इस ओर ध्यान देते हुए मुसलमानों के आज के हालात और उनकी समस्याओं का पता लगाने और उनका निदान करने के लिए योजना बनाने के आशय से आईसीएसएसआर को सर्वेक्षण का काम सौंपा है। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि हालांकि यह काम मुसलमानों की समस्याओं और उनके निदान के लिए किया जा रहा है, पर इसमें यह भी ध्यान दिया जाएगा कि इन क्षेत्रों में या क्षेत्रीय व्यवसायों व उद्योग धंधों में मुसलमानों के फायदे के लिए किए जा रहे काम का फायदा उनके साथ काम करने वाले गैर-मुस्लिमों को भी मिले।

‘राष्ट्रीय सहारा’ दिल्ली दिनांक 22.10.07 से साभार

हिन्दुओं की पहचान नष्ट करने का जेहाद

मुसलमानों में जेहाद एक पवित्र कार्य है। लादेन भी कहता है कि वह कुप्रफ के विरुद्ध जेहाद कर रहा है। तालिबान को भी ऊपर वाले से यह लाइसेंस मिला है कि वह काफिरों की खबर ले और इस्लामी व्यवस्था कायम करे। कुछ कट्टरपंथी यह समझते हैं कि हिन्दुओं, यहूदियों और ईसाइयों को कैसे भी हानि पहुँचाई जाए, विकल्प अनेक हैं। चाहे सामूहिक नरसंहार हो, उपद्रव हो, हमला हो या बम विस्फोट, सब कुछ जेहाद की श्रेणी में आता है। इस जेहाद के साथ-साथ एक और जेहाद पूरे देश में फैल रहा है वह है लविंग जेहाद यानि हिन्दू युवतियों की पवित्रता को भंग करना और फिर उनके साथ विवाह रचाकर इस्लाम स्वीकार कराना एक तीव्र फैलते जेहाद का एक हिस्सा हो गया है।

आश्चर्य की बात है कि अनेक कथित हिन्दू राजनेताओं की पारिवारिक युवतियों को मुस्लिमों द्वारा भ्रष्ट कर दिया गया। अयोध्या रथ यात्रा के समय भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने जिस सलीम नामक मुस्लिम युवक को अपना रथ चालक बनाया था, उसने चार वर्ष पश्चात् आडवाणी की उच्च शिक्षित भतीजी से विवाह कर लिया। श्रीमती शीला दीक्षित की फत्री इसरार नामक दूध विक्रेता के प्रेम में ऐसी फंसी कि उसने अपनी सारी पारिवारिक मर्यादाओं को तिलांजलि देते हुए उससे विवाह कर लिया। पूरे देश में एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है। देश का अर्थ केवल एक मानचित्र नहीं है, उसकी अपनी पहचान है, उस पहचान को चारों ओर से नष्ट किया जा रहा है, हिन्दू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का क्रम भी जेहाद का अंग है।

'अग्निगामी' साप्ताहिक, मुजफ्फरनगर, 22.10.07 से साभार

इस्लामी आतंकवाद / नक्सलवाद

वेबसाइट के जरिए युवाओं तक पहुँचा हाईटेक अल कायदा

इंटरनेट पर 100 से अधिक अंग्रेजी की ऐसी वेबसाइटें हैं जिनमें कार बम विस्फोट और अन्य आतंकवादी हमलों के वीडियो हैं। अल कायदा तथा अन्य कट्टरपंथी समूह इराक युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोप में रह रहे मुस्लिम युवाओं की नाराजगी को भुना रहे हैं और इन वेबसाइटों के जरिए तथाकथित जिहाद का संदेश फैला रहे हैं।

'द न्यूयार्क टाइम्स' ने आतंकवाद विशेषज्ञाओं के हवाले से प्रकाशित एक खबर में कहा है कि कट्टरपंथियों की इस सामग्री और उनके साक्षात्कारों का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उग्रवादी युवा अमेरिकी और यूरोपीय मुसलमानों की इराक युद्ध तथा इस्लाम की छवि पर हमले को लेकर उद्वेलित भावनाएं जाहिर करने की अपील कर रहे हैं। अखबार के अनुसार पहले सामग्री अरबी में और फिर अंग्रेजी में तैयार की गई। भर्ती के लिए कई भाषाओं में अपील की गई है। 39 पृष्ठों की फस्तिका के एक अंग्रेजी एवं इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में महिलाओं से पश्चिम के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील की गई है।

ऐसे ही एक वेबसाइट में यूरोपीय ईसाइयों के एक समूह 'राकन बिन विलियम्स' का जिक्र है जिसने अल कायदा का अनुसरण किया और ईश्वर से वादा किया कि वह शैतानी ताकतों से बदला लेगा। कार बम हमलों के वीडियो पश्चिमी साइट्स जैसे यू ट्यूब आदि में उपलब्ध हैं। अलकायदा के वीडियो के 21 वर्षीय जर्मन प्रशंसक अबू सलेह के हवाले से खबर में कहा गया है कि यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे आप हॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहे हों। सलेह बर्लिन के विभिन्न इंटरनेट कैफे में सप्ताह में दो बार केवल नई रिलीज देखने के लिए ही जाता है।

'राष्ट्रीय संहारा' दिल्ली दि. 16.10.07 से साभार

शहरों का रुख करने वाले नक्सली हाईटेक हुए

नक्सलवादियों ने भी गांव और जंगल छोड़ शहरों का रुख कर लिया है। अपनी आर्थिक ताकत मजबूत करने के साथ-साथ नक्सली अपने को हाईटेक करने में तेजी से जुटे हैं। इतना ही नहीं वह अपनी गतिविधियों के जरिए कमाई गई बड़े पैमाने पर राशि का निवेश भी कर रहे हैं। तकरीबन एक दर्जन वेबसाइट के माध्यम से नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी खुफिया एजेंसी के हाथ लगी है।

खुफिया एजेंसियों के अनुसार देश में फैले कई नक्सली संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन वेबसाइट के जरिए कर रहे हैं। खुफिया ब्यूरो के संयुक्त टास्क फोर्स फिलहाल रेड डायरी डॉट कॉम, नक्सलवॉच डॉट कॉम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादीद्ध डॉट कॉम जैसी वेबसाइटों की जानकारी मिली है।

खुफिया सूचना के अनुसार नक्सलवादी इन वेबसाइटों के जरिए लोगों से उनका विचार लेती रहती है और जिनके विचार उनकी विचारधारा से मिलते हैं उसे अपने संगठन में लाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं झारखंड में हथियारों के जखीरे के खेप भी वेबसाइट के जरिए पहुँचाने की जानकारी नक्सलियों ने अपने साथी को दी थी। इसकी भी जानकारी इस टास्क फोर्स को मिली है।

नोएडा, गुड़गांव सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों में नक्सलियों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी तथा अन्य मदों में निवेश किया जा रहा है। खुफिया एजेंसी इस दिशा में अपनी जानकारी इकट्ठा करने में लग गई है कि नक्सलियों ने कहाँ-कहाँ और कितना धन का निवेश किया है।

र र र र र - छोड़ दिया गया भाग

'राष्ट्रीय सहारा' दिल्ली दि. 15.10.2007 से साभार

जेहादी व सिख आतंकवादियों की करतूत

यहाँ शहर के एक सिनेमा हाल में कल रात हुए बम धमाके की जाँच कर रहे अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस विस्फोट को सिख आतंकवादियों और जेहादी समूहों ने मिल कर अंजाम दिया। अधिकारियों ने विस्फोट में आरडीएक्स के इस्तेमाल की संभावना से भी इंकार नहीं किया है। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऑडिटोरियम की ऊँची छत से भी लटकते हुए मानव अंग पाए गए।

इस सिलसिले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने विस्फोट में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को दो-दो लाख और घायलों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि कुछ वर्षों के अंतराल के बाद प्रदेश में हुए बम धमाके राज्य में आतंकवाद के फिर से सिर उठाने का संकेत हैं।

राज्य फलिस की खुफिया शाखा के डीआईजी जगदीश मित्तल ने कहा कि विस्फोट जेहादी समूहों और बब्बर खालसा इंटरनेशनल की साठगाँठ का नतीजा हो सकता है। अब तक किसी भी आतंवादी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है।

एनएसजी व फारेंसिक विशेषज्ञों का दल सिनेमा हाल से मिले साक्ष्यों की छानबीन में जुटा हुआ है। विस्फोट की तीव्रता काफी अधिक थी और साक्ष्यों की शुरुआती जांच में इस बात के पर्याप्त संकेत मिले हैं कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था। तीन हफ़ते पहले फलिस ने पंजाब में 500 कि.ग्रा. आरडीएक्स जब्त किया था। विस्फोट

की जांच का एक और पहलू यह भी है कि यह उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को डराने का प्रयास है क्योंकि पंजाब के श्रमिक क्षेत्र पर इन्हीं प्रदेशों का दबदबा है।

‘राष्ट्रीय सहारा’ दिल्ली दि. 16.10.07 से साभार

इस्लाम

गोकशी में लिप्त तीन को गांव से निकाला

गोकशी जैसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए पंचायतों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रविवार को गांव चांदफर में हुई महापंचायत ने गोकशी में लिप्त तीन लोगों को गांव से निकालने का फरमान सुना दिया। इसके अलावा तीन लोगों पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। महापंचायत में हिन्दू व मुस्लिम दोनों समुदाय के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

ज्ञात हो कि गांव चांदफर में 30 अक्टूबर की रात को कुछ लोगों ने तीन गायों की हत्या कर दी थी। इसे लेकर अगले दिन गांव चांदफर व आसपास के गांवों के लोगों ने जमकर हंगामा किया और फलिस से दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। फलिस ने गांव चांदफर निवासी शकील, अब्बू उर्फ तैयुब, शेरदीन, रसूल मोहम्मद, पप्पू खां व उत्तर प्रदेश निवासी मोना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से शेरदीन, रसूल मोहम्मद व शकील को गिरफ्तार कर लिया गया था। तीन दिन तक अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर चार नवम्बर को गांव चांदफर में आसपास के गांवों के गणमान्य लोगों की पंचायत हुई। पंचायत में फलिस को फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। साथ ही 11 नवम्बर को महापंचायत करने का फैसला किया गया।

रविवार को गांव चांदफर में श्रीचंद शर्मा की अध्यक्षता में महापंचायत हुई। श्रीचंद ने बताया कि महापंचायत में मुस्लिम व हिन्दू समुदाय ने सर्वसम्मति से दो अहम फैसले किए। फैसले के अनुसार शकील, अब्बू उर्फ तैयुब को ‘गांव निकाला’ दिया गया। इनमें मोना भी शामिल है। इसके अलावा शेरदीन, रसूल मोहम्मद व पप्पू खां पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की राशि गोशाला को दी जाएगी। महापंचायत शांतिपूर्ण हुई। महापंचायत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना छांयसा प्रभारी सुंदर सिंह फलिस बल के साथ मौजूद थे।

‘दैनिक जागरण’ दिल्ली दि. 12.11.07 से साभार

धार्मिक यात्रा की आड़ में दवाओं का कारोबार

पवित्र हजयात्रा की ओट लेकर देश से यौनशक्तिवर्धक दवाओं व तंबाकू उत्पादों का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के हज टर्मिनल पर शनिवार को सेक्स संबंधी दवाओं और गुटके के 18 बोरे जब्त किए गए। इसके बाद केन्द्रीय हज कमेटी ने कोई भी कामर्शियल आइटम ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

हज टर्मिनल पर यात्रियों के सामान की तलाशी लेने पर यौनशक्तिवर्धक दवाओं और गुटकों का ढेर बरामद किया गया। यह सामान हज कमेटी ने रोक लिया। इसके अलावा एक यात्री के पास से 120 जोड़ी लेडीज एवं इतने ही जेंट्स सूट मिले। दरअसल ऐसी वस्तुएं भारत में काफी सस्ती हैं, लेकिन सऊदी अरब में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मसलन एक गुटका जो यहाँ डेढ़-दो रुपये में मिलता है, उसकी सऊदी अरब में एक रियाल, लगभग 11 रुपये कीमत है। सेंट्रल हज कमेटी के सदस्य मौलाना मोअज्जम ने बताया कि एक यात्री को 45 किलो सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन लोग ज्यादा सामान ले जाने की कोशिश करते हैं। इनमें कामर्शियल आइटम भी शामिल हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों पर हज कमेटी जुर्माना लगा सकती है। **शरियत में प्रावधान :** मौलाना मुफ़्ती अनीस आजाद कासमी कहते हैं कि कोई यात्री हज के दौरान तिजारत के लिए जायज वस्तुओं को ले जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वह शरियत का गुनहगार नहीं होगा। हालांकि जिस देश में वह रहता है और जिस देश की यात्रा पर जा रहा है, दोनों के कानून का पालन करना उसका फर्ज है। लिहाजा यात्रियों को इस तरह के काम से बचना चाहिए। हां, गुटका ऐसा आइटम है जिसे खाने की इजाजत शरियत नहीं देती, लिहाजा जो इसका कारोबार करेगा, वह यकीनन गुनहगार होगा।

‘दैनिक जागरण’ दिल्ली दि. 25.11.07 से साभार

टिप्पणी : ‘धार्मिक यात्रा’ शब्द के बजाए ‘मजहबी यात्रा’ लिखा जाना चाहिए क्योंकि इस्लाम मजहब है, धर्म नहीं।

दारुल उलूम में विदेशियों का बार-बार आना ठीक नहीं

किसी-न-किसी बहाने विदेशी दूत और अफसरों का दारुल उलूम आगमन अब इस्लामिक जानकारों को चुभने लगा है। इनका मानना है कि गैर जरूरी तरीके से विदेशियों का यहां आना उचित नहीं है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद दारुल उलूम के प्रति खास तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन के अफसरों और पत्रकारों में जिज्ञासा बढ़ी है। इन्हीं के जवाब ढूंढने के वास्ते यहां विदेशी शिष्टमंडल आने शुरू हुए। न्यूयार्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका व ब्रिटिश दूतावास के अधिकारियों सहित ब्रिटिश पत्रकारों का गाहे-बगाहे विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम में किसी-न-किसी बहाने भ्रमण करने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि दारुल उलूम ने प्रत्येक बार विदेशी मेहमानों को उनके सवाल का विस्तार से जवाब देकर संतुष्ट भी किया है। तीन वर्ष में दारुल उलूम में आने वाले विदेशी मेहमानों की बात करें तो 23 सितम्बर 2004 को अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ राबर्ट ब्लैक, इसके बाद 7 जुलाई 05 को ब्रिटेन दूतावास के प्रथम सचिव एलेकजेंडर इंवास और हाई कमीशन का प्रतिनिधिमण्डल तथा इसके बाद दोबारा से मार्च 06 में अमेरिकी दूतावास का प्रतिनिधि-मंडल आया। 1 मई 06 को बीबीसी पत्रकार डेविड विलसन, मोनी क्लार्क, 25 सितम्बर 06 को मदरसा पर वृत्तचित्र फिल्म बनाने वाली ब्रिटिश पत्रकारों की टीम तथा अगस्त 07 को ब्रिटेन दूतावास के राजदूत डिक स्टेग, 1 जुलाई 07 को चर्चित मेगजीन टाइम्स के पत्रकारों की टीम तथा हाल ही में 15 नवम्बर 07 को अमेरिकी दूतावास के राज्य विभाग के अधिकारी डगलस मैकेक, राजनैतिक अधिकारी जेम्स जीरा आदिने दारुल उलूम पहुंचकर यहाँ दी जा रही शिक्षा एवं कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया।

'दैनिक जागरण' दिल्ली दि. 18.11.07 से साभार

बंदों की बंदगी में फरक न हो

विभिन्न धर्मों या एक ही धर्म के विभिन्न संप्रदायों में वैचारिक टकराव फरानी बात है, लेकिन जब यह खबर नीले पर्वतों, खूबसूरत वादियों और आसमान छूते देवदारों की धरती से आती है तो अहसास थोड़ा जुदा होता है। गोली-बारूद से कांपते कश्मीर के बुजुर्गों व जवानों में इस समय जो बौद्धिक टकराव चल रहा है, आइए उसका जायजा लेते हैं।

सूफी, बरेलवी, देवबंदी या कुछ और। श्रद्धा अपनी, आस्था अपनी। उत्तरी कश्मीर के बारामुला कस्बे के शेख हिलाल और उनका भाई अशरफ अब अलग हैं। इंजीनियर भाइयों में विवाद विचारधारा का है। हिलाल सूफी संतों की जियारत करते हैं, तो अशरफ देवबंदी विचारधारा से प्रभावित हैं। कश्मीर में शायद ही कोई मुहल्ला बचा है, जहां इस्लाम की विभिन्न धाराओं के बीच बहस-विवाद न हो।

इस्लाम के शोधार्थी अशाफाक अहमद के मुताबिक पिछले दो दशकों में कश्मीर में फराना सूफी मत कमजोर हुआ है, जबकि अहल-ए-हदीस, जमात-ए-इस्लामी, देवबंद, तबलीगी जमात और शहाफी विचारधारा के मानने वाले बढ़े हैं। मस्जिदों पर कब्जे को लेकर इनके बीच की लड़ाई अदालत तक भी पहुँची। कश्मीर के मुफ्रती-ए-आजम बशीरुद्दीन सूफी का कहना है कि आतंकवाद के दौर में ही वादी में दूसरी विचारधाराओं ने अपनी जड़ें मजबूत कीं— 'यहां हमेशा सूफीवाद रहा। अन्य संप्रदायों का 20 सालों में प्रचार खूब हुआ। हर गली में जमात, अहल-ए-हदीस या देवबंद का मदरसा जरूर दिखेगा। कट्टरपंथियों का हिंसक आन्दोलन में दबदबा रहा। मुझ पर भी उन्हीं लोगों ने 1990 के दशक में हमला कराया। कुछ लोगों ने मुझे अपनी विचारधारा बदलने को कहा।' एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले अब्दुल करीम वानी ने स्वीकार किया कि कभी सूफीवाद में मेरा यकीन था, लेकिन अब नहीं। उधर, अब्दुल करीम के शिक्षक पिता मोहम्मद नियाज सूफी मत के हैं। वे बताते हैं कि सूफी संत ही यहां इस्लाम की रोशनी लाए। हिन्दू और सिख भी इन्हें मानते हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडी सेंटर के नसीम हमीद रफियाबादी के अनुसार 'युवाओं में यह बदलाव 'रिएक्शनरी' है। मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में प्रचार होता है, तो लोग अब इस्लाम के बारे में पढ़ने लगे हैं।' तबलीगी जमात के एक सदस्य ने कहा कि पहले लोग हमें गंभीरता से नहीं लेते थे। जब यहां बंदूक नहीं थी तब हमने हजरत बल में एक जलसे की कोशिश की। लेकिन दरगाह के इमाम ने रोक दिया। लेकिन बीते 20 सालों में बहुत कुछ बदला है।

शब्बीर अहमद मानते हैं कि आतंकवाद के दौर में सूफी परम्परा में विश्वास करने वाले लोग चुप रहे, जबकि अन्य विचारधाराओं वाले एकजुट हो गए। वकील रियाज अहमद ने कहा कि कश्मीर में इस्लाम की धारा सूफी है। अन्य विचारधाराएं सऊदी अरब और खाड़ी देशों से निकल रही हैं। वहीं से पैसा भी खूब आ रहा है। उधर, अहल-ए-हदीस की प्रदेश इकाई के प्रमुख मौलाना शौकत ने कहा कि अब ज्यादा जागृति है।

‘दैनिक जागरण’ दिल्ली दि. 25.11.2007 साभार

कानून, समाज और साहित्य

पवन चौधरी ‘मनमौजी’

कानून और साहित्य समाज की दो भुजाएं हैं। एक इसकी सुरक्षा-सुव्यवस्था के लिए और दूसरी इसे सजाने-संवारने, स्वस्थ-सुंदर बनाने के लिए। कानून में दिमाग का अधिक महत्व है और साहित्य में दिल का। कानून का अभिप्रायः वास्तविक कानून और कागजी कानून से है। पहले का उपयोग कचहरी के अंदर होता है और दूसरे का कचहरी के बाहर। कचहरी से बाहर का आशय विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सचिवालय, सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि से है, जिसे सामूहिक तौर पर ‘कार्यपालिका’ की संज्ञा दी जा सकती है। कचहरी के अंदर का वास्तविक कानून है, जिसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। कागजी कानून आदर्श है और वास्तविक कानून यथार्थ। दूसरे शब्दों में कानून सिक्के के दो सच हैं—एक कचहरी के अंदर का और दूसरा कचहरी के बाहर का। वास्तविक कानून का वास्ता न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं समेत कानून पीड़ितों से पड़ता है, जबकि कागजी कानून का विधि प्राध्यापकों, विद्यार्थियों, सलाहकारों कर्मचारियों से। इसी प्रकार, साहित्य में साहित्य-सृजन एवं पत्रकारिता दोनों शामिल हैं। सृजन में अनेक विधाएं सम्मिलित हैं।

कानून और साहित्य के संबंध में कई धारणाएं-मान्यताएं हैं। कानून बड़ा कठोर, निर्दयी निर्मम होता है कानून मोम की नाक है जिसे जिधर चाहा मोड़ लिया। कागजी कानून में कानून के सफेद कबूतर उड़ते प्रतीत होते हैं, और वास्तविक कानून में प्रायः कानून के काले कौवे। कागजी कानून का उपवन सुखद-आनन्दमयी होता है और कचहरी कानून का जंगल जी का जंजाल, कष्टदायक, अनिश्चित आलम आदि। अमीर लोगों के लिए कानून का शिकार करने के लिए मनोरंजन का मनोरम स्थान। कचहरी-कानून की राह पथरीली-खर्चीली-खुशामदी होती है, जिस पर कानून की गति कछुए या हवाई जहाज समान होती है। कानून का रथ साक्ष्य के कमजोर पहियों पर चलता है। जैसा व्यक्ति वैसा कानून के जखीरे भी स्पष्ट दिखायी दे सकते हैं। इसी प्रकार, साहित्य के बारे में भी कई सत्य हैं। मसलन, साहित्य कोमल होता है। कठोर भी कम नहीं होता है—तलवार से भी अधिक धारदार, प्रभावशाली। साहित्य समाज की मूँछ होती है, पूँछ नहीं। साहित्य-समाज का पहरेदार एवं पथ-प्रदर्शक होता है। पालतू पिल्ला, पिछलग्गू अथवा पिट्टू नहीं। कानून का दरोगा दिमाग होता है और साहित्य का स्वामी दिल। कानून और सच्चे साहित्यकारों की दालरोटी-दाल, मक्खन-मलाई खाने वलों की सोच एवं व्यवहार में अंतर होता है। किसी में कम किसी में अधिक, पर होता अवश्य है। और इस सत्य को झूठलाना भी सहज नहीं है कि दिल और दिमाग दो कुदरती किनारे हैं। एक का दूसरे में अतिक्रमण आसान नहीं है। प्रश्न है क्या न्यायिक क्षेत्रों में दिमाग और दिल नामक दो घोड़ों के रथ पर सवार होना एवं रहना संभव है? सहारनफर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का उत्तर ‘नहीं’ में था। अपने मत के समर्थन में उन्होंने एक उदाहरण दिया था। एक वकील की रुचि साहित्य में भी थी जिसके कारण उसकी वकालत चल नहीं रही थी। प्रभाकर जी ने उसको साहित्य के प्रति मोह को विराम देने की सलाह दी। सलाह मानते ही, उसकी वकालत न केवल चल निकली बल्कि सरपट दौड़ने लगी। दूसरा उदाहरण राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति शिव कुमार शर्मा का हो सकता है। न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति से पूर्व वह अधिवक्ता थे—योग्य परिश्रमी एवं अनुभवी। उनकी कलम और कंठ में भी कोई कमी नहीं थी। उनको मंच पर सुनते समय श्रोतागण मुग्ध हो जाते थे, जिनमें एक लेखक भी था। पर कलम-कंठ ही उनके न्यायाधीश बनने में कांटा थे। किसी शुभचिंतक की सलाह पर उन्होंने कलम-मंच को त्याग दिया। केवल कानून तक सीमित रखा। कुर्सी के सामने कलम की क्या औकात। कुछ वर्ष पश्चात् उन्होंने मंजिल पा ली। आज भी वह कलम से इश्क फरमा तो लेते हैं, पर कभी-कभार, चुपके-चुपके। उपर्युक्त अवसर मिलने पर खुले आम भी इसे करने से नहीं चूकते। भिन्न प्रकार का तीसरा उदाहरण दिल्ली में एक वकील-साहित्यकार अथवा साहित्यकार-वकील का लिया जा सकता है। कुदरत की कृपा के कारण एक इस अधिवक्ता का कानून और कलम दोनों में निर्विवाद कमाल था—निष्ठापूर्ण, योग्य, अनुभवी, बहुमुखी

व्यक्तित्व का स्वामी, ईमानदार, सच्चा, स्वाभिमानी, मूल्यों का फराना आशिक, वगैरह-वगैरह। उसको न्यायाधीश के पद पर केवल उन्हीं कारणवश नियुक्त नहीं किया कि उसके हाथ में कलम थी, वह स्वतंत्र प्रवृत्ति का था और स्वाभिमानी तथा न्यायप्रिय भी कम नहीं था। हां, इतना अवश्य है कि वह व्यावहारिक नहीं था। इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि अदालत-वकालत में साहित्यकार नहीं हुए हैं-आज भी उनका अकाल नहीं है। केवल उदाहरण के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश वी.आर.कृष्णा अय्यर के दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डॉ. वी.एस.देशपांडे, न्यायाधीश जलपाल सिंह आदि। दिल्ली की अधिनस्थ अदालतों के लगभग ढाई सौ जजों में एक दर्जन न्यायिक अधिकारी कानून-कलम के धनी हैं, जिनकी छवि पर किसी प्रकार की कोई आंच भी नहीं है। न्यायमूर्ति अय्यर एवं जसपाल सिंह के निर्णय तो कवितात्मक होते ही थे। इसके लिए वे आज भी प्रसिद्ध हैं। अब एक अति नाजुक-रोचक प्रश्न क्या लेखक न्यायिक अधिकारीगण अधिक ईमानदार, परिश्रमी, योग्य, कानून-कुर्सी के प्रति तनिक अधिक वफादार होते हैं? सामान्य नग्न सत्य यह जान पड़ता है कि वर्तमान वातावरण में व्यवस्था केवल व्यवस्था को पसंद करती है, व्यक्ति को नहीं, व्यवस्था में व्यक्ति का प्रवेश लगभग निषेध है। प्रवेश पाने के पश्चात् व्यक्ति बने रहना और चुनौतीपूर्ण है। और यह भी झूठ नहीं है कि व्यवस्था में सुधार-व्यवस्था द्वारा कम अपेक्षित है, व्यक्ति द्वारा अधिक। जैसा व्यक्ति वैसी व्यवस्था। कारण व्यवस्था निर्माण नहीं करती, संभवतः न कर सकतीः व्यक्ति व्यवस्था का निर्माण कर सकता है, और अकसर करते हुए पाया भी जाता है।

न्यायमूर्ति अय्यर, जसपाल सिंह, स्व. वी.एस.देशपांडे, शिवकुमार शर्मा, प्रो. उपेन्द्र बख्शी, एस.सहाय ऐसे अनेक जाने-माने हस्ताक्षर हैं जिनका उपर्युक्त मत को समर्थन मिला है। इसलिए कहा जा सकता है कि समाज की स्वस्थ-सृष्ट-सार्थक प्रगति की डोर दिल एवं दिमाग नामक दोनों हाथों को सौंपी जानी चाहिए। तभी कानून के आकाश को कानून की पतंग छू सकती है, अन्यथा नहीं-कभी नहीं। ऐसे में एक विचारणीय प्रश्न का सिर उठाना स्वाभाविक है : क्या न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियों में समाज के दो भुजाओं वालों को-अन्य प्राथमिकताओं के समान प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, ताकि समाज में न्याय का सर्वत्र प्रकाश हो, अन्याय का विनाश होः विधि एवं न्याय समाज की प्रगति का नवीन पथ-प्रदर्शक बने? और एक बार नहीं बारम्बार बिगुल बजाते रहना चाहिए तब तक जब तक विधि एवं न्याय के सत्ताधारियों के कान पर कोई जूँ नहीं रेंगती।

पवन चौधरी 'मनमौजी'

चौधरी कुटीर, ई-31, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली-110 015

सूक्तियां

□ सम्मानित होने के लिए कानून को सम्मान के योग्य होना चाहिए। उसे न्यायसंगत होना चाहिए और न्यायपूर्वक ही लागू भी होना चाहिए।

-रिचार्ड निक्सन

▣ विदेश नीति यथार्थवादी विषय है और उसका निर्धारण मुख्यतः राष्ट्र के हित की दृष्टि से ही होना चाहिए।

-सुभाष चन्द्र बोस

▣ हमारे न तो कोई शाश्वत मित्र हैं और न कोई स्थायी शत्रु। शाश्वत तो हमारे हित हैं और उन हितों का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है।

-पामस्टन

▣ श्रेष्ठता कुसंग से डरती है। नीचता ही उसे बन्धु मानकर उससे घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देती है।

-तिरुवल्लुवर

▣ लड़ें क्यों हिन्दुओं से हम यहीं के अन्न से पनपे हैं हमारी भी दुआ ये है कि गंगा जी की बढ़ती हो

- अकबर

,साभार : 'बृहत् विश्व सूक्ति कोश' संपादक डॉ. श्याम बहादुर वर्मा)

राष्ट्र वन्दना

कविता ;धान्वन्तरि त्रयोदशी सं. 2064 वि.द्ध

जय भारतम्

नमामि भारतमातरम्

जय भारतम्, जय भारतम् ।।

हिन्दुकुशतः ब्रह्मदेशम्
आलंकातः त्रिविष्टपम्
मातः तव वृहत्शरीरस्य
उत्तालतरंगित-सागरः
करोति चरण-प्रक्षालनम् ।
नमामि भारतमातरम् ।

नमामि भारतमातरम्

जय भारतम्, जय भारतम् ।।

त्वं देवभूमिः त्वं फण्यभूमिः
त्वं विश्वगुरुः त्वं तपोभूमिः
)षयो महर्षयः देवसम्राजः
वीर-वीरांगनानाम् जननीम्
कोटि-कोटि देवैः पूरिपूजिताम् ।

नमामि भारतमातरम्

जय भारतम्, जय भारतम् ।।

गीतानि देवैः बहुगीतकानि
भारते प्राप्तं जन्म फनीतम्
तव चरणो श्रद्धया पूजितौ
मुण्डमालमपि तुम्यमर्पितम्
फनर्फनः प्राणैः सुपूजनम् ।

नमामि भारतमातरम्

जय भारतम्, जय भारतम् ।।

डॉ. रवीश कुमार
227, मोती महल, राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ-226 001

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पहले

हिन्दी भाषण का अंश

ब्रह्म लोक की वार्ता

एस सेतुर्विधरण असम्मे दायलोकानां –

नैनं सेतु – रहो रात्रे तरतः

नं. शोको न जरान मृत्यु एतं सेतुं तीत्वा अन्धः सन्–

अनन्धो भवति विद्धःसन अविद्धो भवति

उपहायीसन् अनुपाती भवति

सुकृद्भिभातो ह्येष ब्रह्मलोक ।

यह सेतु सर्व लोगों को धारण करने के लिए है संभेद को दूर करने के लिए है, अहोरात्रि यह सेतु को लंघन कर सकता नहीं, शोक जरा मृत्यु इसको लंघन कर सकता नहीं, इसको पार हो करके अंध अनंध हो जाते हैं, पापी निष्पाप हो जाते हैं, शोकार्त विगत शोक हो जाते हैं। यह ब्रह्मलोक उदय मात्र और अवसान को प्राप्त होता नहीं।

प्रस्तुति : कमल किशोर गोयनका, साभार : 'साहित्य अमृत' मासिक, 4/19 आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002

राजनीति के दोहे

महाफरुष बनने चले राजनीति में लोग

लेकिन शोषक बन गए कर सत्ता का भोग

कथनी करनी में हुआ भारी अंतर आज

कहने को सेवा करें मन में चाहें राज ।

जनता बुद्ध बन रही राजनीति के हाथ

दुःख सहकर भी रात-दिन नहीं छोड़ती साथ ।

योगी से भोगी बने राजनीति के संत

देशभक्ति के भाव का पूर्ण हो गया अंत

भ्रष्ट आचरण देश में फैला चारों ओर

जनता के दुःख दर्द का कहीं ओर नहीं छोर ।

राजनीति के खेल ने किया खोखला देश

रहते हैं इस देश में लेकिन बैंक विदेश ।

राम राज के नाम पर जो बोए थे बीज

वे सब कड़वे हो गए फल सब पसीज ।

निर्धन से राजा बने कार कोठी भूखंड

जन सेवा के नाम पर फैल रहा पाखंड ।

कैसे-कैसे आ गए राजनीति में लोग

उजले-उजले वेश में काले काले ढोंग ।

डॉ. मित्रेश कुमार गुप्त – अनुकंपा भवन, 19 तिलक मार्ग, मेरठ

पुस्तक समीक्षा

साहित्य एवं दृक्-श्राव्य सेवा न्यास

हमारे प्रकाशन संस्थान ने एक महाफरुष का जीवन चरित्र पध्येय समर्पित लोकनेता श्री जगन्नाथराव जोशी के नाम से फस्तक रूप में प्रकाशित किया है। स्व. श्री जगन्नाथराव जोशी कर्नाटक में संघ-प्रचारक थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के पश्चात् उन्हें कर्नाटक प्रदेश में भारतीय जनसंघ के संगठन का कार्य सौंपा गया। मराठी, कन्नड़, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रभावी रूप से अपनी तर्कशैली और व्यंग्य की अनुपम धारा से वे घण्टों श्रोताओं को बांध रखने में समर्थ थे। वे गोवा मुक्ति आन्दोलन के प्रमुख सेनानी रहे और गोवा के फर्तगाली कारावास में दो वर्ष बन्दीवास भी किया।

उनके अनन्य मित्र विश्व हिन्दू परिषद के ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्री सदानन्द जी काकड़े ने अपने सहयोगी विद्वान, साहित्यिक, महाराष्ट्र के एक भाजपा कार्यकर्ता डॉ. श्री अरविन्द लेले से आग्रहपूर्वक मराठी में श्री जोशी का जीवन चरित्र लिखवाया। वह महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित एवं प्रशंसित हुआ। श्री सदानन्द जी ने उसे कन्नड़ में अनुवाद कराकर प्रकाशित किया।

उक्त फस्तक का हिन्दी अनुवाद श्री ओंकार भावे, दिल्ली ने किया। सुन्दर-आकर्षक मुद्रण सजिल्द यह अब विक्री के लिए उपलब्ध है। मांग पत्र के साथ ड्राफ्ट 'साहित्य एवं दृक्-श्राव्य सेवा न्यास' के नाम नई दिल्ली में प्राप्तव्य भेजें।

फस्तक का मूल्य	200 रुपये केवल
5-10 फस्तक तक	10 :छूट
11-24 फस्तक तक	20 :छूट
25 एवं उससे अधिक फस्तक तक	25 :छूट

डाक अथवा पार्सल आदि भेजने के लिए अतिरिक्त का मूल्य अतिरिक्त।

न्यास का पता : संकटमोचन आश्रम, सेक्टर-6, रामकृष्णफरम, नई दिल्ली-110 022

यथा नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रमाप्य
गच्छन्ति नाम रूपे विहाय ॥
तथा विद्वान्नाम रूपाद्विमुक्तः ।
परात्परं फरुषमुपैति दिव्यम् ॥

जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में पहुंच, विलीन होकर अपने नाम और रूप छोड़ देती हैं, वैसे ही ज्ञानी लोग अपने नाम और स्वरूप की आसक्ति, देहाभिमान को त्याग कर उस दिव्य फरुष-भगवान में समा जाते हैं। अर्थात् आत्मतत्त्व अथवा निज स्वरूप की अनुभूति करते हैं।

'संस्कृत सुभाषित सुमन' प्रकाशक : मेघराज, कालकाजी, दिल्ली

फस्तक : पिछड़े क्यों मुसलमान

लेखक : शंकर शरण

प्रकाशक : सूर्य प्रकाशन मंदिर दाऊजी रोड, नेहरु मार्ग बीकानेर

मूल्य : एक सौ साठ रुपये

मुसलमानों को एक अच्छा वोट बैंक मानते हुए उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के विभिन्न हथकण्डे राजनीतिक दल अपनाते हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट भी बहुत कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। राजनीतिक सड़क की बू इस रिपोर्ट से स्पष्ट

आती दिखाई पड़ती है। मुसलमानों को अन्य पिछड़ी जातियों को ही तर्ज पर प्रकारान्तर से आरक्षण देने की मुहीम का समर्थन करती इस रिपोर्ट की राजनीति को समझना बुद्धिजीवी समाज के लिए नितान्त आवश्यक है।

ऐसे समय में जब मुसलमानों को लेकर राजनीतिक खिलवाड़ अपने शबाब पर हो तब शंकर शरण जी की फस्तक 'पिछड़े क्यों मुसलमान' का आना निश्चित ही स्वागत योग्य है। अपनी इस फस्तक में लेखक ने कुल 'तेरह' निबन्धों के माध्यम से मुसलमानों के पिछड़े होने की बात को सहज स्वीकार करते हुए उसके कारणों पर राजनीति से ऊपर उठकर अत्यंत ही विधेयवादी दृष्टि से विचार किया है।

लेखक की मान्यता है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। आरंभ से ही इनके धार्मिक नेताओं ने सामाजिक विकास का विरोध इस्लाम के विरुद्ध षड्यंत्र कहकर किया। उनके मार्गदर्शन उलमा की केन्द्रीय भूमिका रही। ये उलमा आधुनिक शिक्षा की बात का सदा से विरोध करते आए हैं। उनके अनुसार जीवन का हर सवाल मज़हब से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ये लोग पोलियो के टीके तक को इस्लाम विरोधी मानकर इसे बच्चों को लगवाने से इंकार करते रहे हैं। इस्लामी पर्सनल लॉ और शरीयत के नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति को इसके विरुद्ध बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं है। वस्तुतः इस्लाम मुसलमानों को स्वयं अपने विवेक से सोचने समझने, लिखने-बोलने की इजाजत नहीं देता। कोई कोशिश करे तो उलमा उसके विरुद्ध फौरन मौत का फरमान जारी कर देते हैं। सलमान रश्दी और तसलीमा नसरीन इसके उदाहरण हैं। इस्लामी पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम लड़कियों और औरतों के साथ ऐसे जुल्म किए जाते हैं जो किसी भी समाज के विकास में बाधक हो सकते हैं। मुस्लिम समाज में व्याप्त अरबी निकाह इसी मानसिकता की धिनौनी उपज है। ऐसा समाज अगर पिछड़ता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उलमा किसी भी काम के लिए फतवे जारी करते हैं जिनका आम मुसलमान चाहे-अनचाहे पालन करता है। शंकर शरण जी के शब्दों में ये ही मुस्लिम समाज के सार्वभौमिक नेता हैं। ऐसी मानसिकता के साथ कितनी प्रगति की आशा की जानी चाहिए?

पाठकों के पत्र

माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय : गर्भवती महिलाओं की गर्भ-अवधि में बैड रेस्ट तथा प्रसव समय शल्य क्रिया के बारे में।

सोम की आहुति अग्नि में पड़ने से नव सृजन होता है। ईश्वरीय कृति मानव समाज तथा परिवार की धरोहर है जिस पर माता-पिता के परस्पर प्रेम समर्पण की मोहर है। मान्यता के अनुसार जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सूत्रानुसार मां को प्राप्त आधार, आहार, विचार के आधार पर गर्भस्थ शिशु को प्राथमिक संस्कार प्राप्त होते हैं क्योंकि गर्भस्थ शिशु माता के रक्त से ही वर्धन-पोषण पाता है। श्रद्धेय पं. मधुसूदन जी ओझा की पितृ समीक्षा के अनुसार शुक्र में 84 अंश होते हैं 28 अंश माता-पिता से तथा शेष 56 अंश सात पीढ़ियों से गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होते हैं।

मुझे एक बार पढ़ने को मिला कि अच्छी नस्ल का घोड़ा प्राप्त करने के लिए संभोग के समय में घोड़ी के सामने अच्छी नस्ल का घोड़ा खड़ा किया जाता है। जब पशु उक्त पथथा दृष्टि तथा सृष्टि से प्रभावित होता है तो कल्पनाओं-आशाओं-आकांक्षाओं के धनी संबंधित फरुष-स्त्री कैसे इससे वंचित रह सकते हैं। हमारे देश का चिकित्सक वर्ग योग्य, विद्वान, सक्षम, समर्थ तथा पूर्णतया उत्तरदायी है। लेकिन अपवादों को नकारा नहीं जा सकता। समाज अपवादों की तरफ ज्यादा शंकालु होता है। बहूसूत्र उपेक्षित हो जाते हैं जैसा कि टीवी चैनलों के ऊपर रोजाना दर्शाया तथा जन मानस को उक्साया-भड़काया जाता है, क्योंकि इसमें उनके व्यावसायिक हित जुड़े रहते हैं। किसी एक की गलती के लिए समस्त वर्ग को लांछित करना किसी स्तर पर शोभायमान नहीं लगता।

देखने में आया है कि सरकारी संस्थानों-अस्पतालों में अधिकतर गर्भवती महिलाओं का सामान्य प्रसव होता है। विभिन्न कारणों से प्राइवेट नर्सिंग होम्स में गई गर्भवती महिलाओं को बैड रेस्ट की सलाह दी जाती है। इस अवधि में महिलाएं टीवी

चैनलों द्वारा सनसनी, हत्या, बलात्कार, अपहरण, आत्महत्या, हिंसा—प्रतिहिंसा पूर्ण फिल्में एवं दृश्य एवं सीरियल देखती हैं। सोचा जा सकता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि का उन पर क्या फल होगा? जबकि मैंने स्वयं कुछ अपने मित्र चिकित्सकों से अपवादों को छोड़कर ऐसा न करने का विनम्र निवेदन किया है। ऐसा भी सुनने में आया है कि **कुछ नर्सिंग होम्स में जहाँ पर गर्भवती महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, आरंभ से अंत तक सामान्य चलता रहता है, न जाने उनको क्या औषधियां सेवन कराई जाती हैं जो अन्त समय में उनको शल्य क्रिया कराने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्या यह जरूरी, मजबूरी या व्यावसायिकता है?** यह देखना—करना संबंधित मंत्रालय एवं विभाग अध्यक्षों का कार्य है। मैं तो मात्र पीड़ा लेखक हूँ पपड़े पीड़ा, सुने पीड़ा, कहे पीड़ा, पर न सहे पीड़ा का आग्रह जन—जन तक पहुँचाने में प्रयासरत रहता हूँ। मेरा किसी से भी व्यक्तिगत पूर्वाग्रह आशा नहीं जुड़ी हुई है।

विनीत
पं. जगदीश लाल शर्मा

बी-48, रघुवीर एन्क्लेव, नज़फगढ़, नई दिल्ली

‘गुजरात का सच’ के संबंध में विहिप द्वारा दिया गया संयुक्त प्रेस—वक्तव्य

दिल्ली। 26 अक्टूबर 2007 तहलका की ‘गुजरात का सच’ नामक सी.डी. चैनल ‘आज तक’ द्वारा लगातार दो घंटे से भी अधिक समय तक प्रसारित करते रहना चैनल की कुत्सित मनोवृत्ति का प्रतीक है। विश्व हिन्दू परिषद इस कृत्य की घोर निन्दा करती है।

घटना के पांच वर्षों के बाद गुजरात में चुनाव के ठीक पहले संदर्भों को तोड़—मरोड़ कर सी.डी. का निरंतर प्रसारण देश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का सोचा—समझा षडयंत्र है। इसके लिए सरकार को चैनल के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। सी.डी. को निरंतर दिखाना और अपनी जिम्मेदारी से भी भागना सामाजिक अपराध है। यह प्रसारण समाचार नहीं, विज्ञापन है। चैनल स्पष्ट करे कि यह विज्ञापन किसका है?

सी.डी. में किसी का चेहरा साफ नहीं दिखता, अतः यह स्पष्ट है कि सी.डी. भ्रामक है। यह ‘गुजरात का सच’ नहीं अपितु ‘गुजरात का झूठ’ है। मूलक्रिया को किसी पूर्वाग्रह के कारण छिपाकर प्रतिक्रिया को बढ़ा—चढ़ाकर प्रलोभन एवं प्रभाव से प्रसारित किया गया है। इस सी.डी. प्रसारण से देश के किसी भाग में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए प्रायोजक और प्रसारणकर्ता ही उत्तरदायी होगा।

यह भी विचारणीय है कि प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा करना कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन, रंगनाथ मिश्र आयोग के सहारे अनुसूचित जातियों के आरक्षण सुविधाओं को छीनना, देश के कुछ राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की होड़, श्रीरामसेतु को तोड़ने की जिद में भगवान राम के अस्तित्व को ही शपथपूर्वक नकारना और अब पांच वर्षों की फरानी घटना को बार—बार प्रसारित करा कर समाज में घृणा फैलाना और यह सब अल्पकाल में ही घटित होना किसी एक ही योजना का हिस्सा सिद्ध होता है।

प्रसारितकर्ता, चम्पतराय, संयुक्त महामंत्री, विश्व हिन्दू परिषद

Seven facts that nail the lies about Gujarat

-B.P.Singhal

The post-Godhra violence was neither ‘genocide’ nor ‘pogrom’ against Muslims. It was communal violence in which Hindus also died, many shot dead by police, says BP Singhal

Late month there was an attempt to revive the secularists’ campaign of calumny against Gujarat Chief Minister Narendra Modi and his Government on the basis of the same old fiction about the post-Godhra violence of 2002. On October 25, Aaj Tak, while broadcasting Tehelka’s ‘sting operation’, harped on the same old refrain that Mr Modi “did not call in the Army until three days had passed”.

When Aaj Tak contacted me to get my response, I told the anchor that the Godhra carnage took place on February 27, 2002, that the Hindu backlash commenced on February 28, and the Army was conducting a flag march on the forenoon of March 1. He cut me short by saying that “this is exactly what we have said, no action was taken by Mr Modi on the 29th, 30th and 31st, thus giving three clear days to the murderers...”. I had to remind him at this point that the date 28th was February 28 and there was no 29th, 30th or 31st in that month. The ‘phono’ was disconnected.

It is imperative that certain facts are stated to prevent the perpetuation of lies being propagated since 2002. Here are some of them:

Fact 1: Shoot at sight orders had been issued by the Government on February 28, 2002, itself. Being an Ex-DGP and a Member of Parliament at that time, I was in touch with the office of DGP Gujarat and the Commissioner of Police, Ahmedabad. I was keen to tell them: (a) Call in the Army at once; and (b) issue “shoot at sight” orders to all officers of the rank of Sub-Inspector and above. It was comforting to learn that the Gujarat Government had already taken both steps by 2.30 pm on February 28. The State Government had also requested for armed police reinforcements from neighbouring States, besides calling for the Army.

Fact 2: On the February 28 police had shot dead 10 Hindus and wounded 16 Hindus.

Fact 3: On the next day, that is, March 1, another 24 Hindus were shot dead and 40 Hindus wounded by the police.

Fact 4: In the entire period of riots, the police had shot dead 80 Hindus and wounded 207 Hindus. But no Delhi-based media showed any interest in reporting these casualties.

Fact 5: The Muslim counter-attack, which commenced from March 1, was no less ferocious. In the first three days alone, of a total of 611 deaths, 101 were caused by police firing. Of these, 61 were Hindus and 40 were Muslims.

Fact 6: As on March 5, as many as 40,000 Hindus had to be given shelter in relief camps. Plenty of media coverage was given to the plight of Muslims in relief camps but no Delhi-based media covered any Hindu relief camps.

Fact 7: In answer to Parliament questions, the UPA Home Minister provided the figures of casualties during the Gujarat riots: 790 Muslims killed, 254 Hindus killed, 2,500 wounded in all and 223 missing. These details nail the lie that what happened in Gujarat was a ‘one-sided affair’: For every three Muslims who died in Gujarat, one Hindu was also killed.

Such heavy casualties in riot control are unprecedented in the entire history of the Indian police. The figures of casualties caused by police firing in the first three days alone indicate the ferocity of police action. Yet, the ‘secular’ parties and their cohorts in media even to this day proclaim unabashedly that Mr Modi ordered the police “to look the other way” to give a free hand to ‘murderers’ for three days. If they have any respect for the truth, they can cross-check the casualties with hospital records. The police is duty bound to carry those killed and wounded in police firing to Government hospitals.

With the Muslim counter-attack commencing from March 1 till the riots were quelled altogether, what took place in Gujarat was a full-fledged Hindu-Muslim riot. It was no “genocide”, “pogrom” or “state terrorism” against Muslims. No “modern day Nero was looking the other way”. The modern day Chief Minister was dealing with the situation as best as was possible with the highly limited forces at his command.

Because of the spontaneous conflagration at scores and scores of locations, it is entirely possible that the police or Fire Brigade may have failed to reach a scene for hours, or, having been spread so thin, the police force that did reach a scene was deterred from intervening by the sheer ferocity of violence at that point in time. But to say that the police was restrained as a measure of Government policy is completely belied by the large number of casualties caused by police firing.

The insane ferocity and brutality with which Ram bhakts, including innocent children and helpless women, were roasted alive at Godhra, set the benchmark for the equally insane ferocity of the Hindu backlash and that was followed by an equally insanely ferocious counter-attack by Muslims.

The Delhi-based media made out as though the whole of Gujarat was in flames. It concealed the fact that of 18,600 villages, 240 municipal towns and 25 districts, the number of places affected by the riots was just 60. Not a single man-day was lost in the 200-odd industrial townships in Gujarat because of the riots. Examinations in schools, colleges and universities were conducted as per schedule during the period of riots.

Irrefutable confirmation that it was a communal riot and not a “genocide” or “pogrom” has come from the verdicts of courts hearing the post-Godhra riot cases. Here are some examples:

(i) The Deccan Herald reported in May 2004: “Conviction of 3 confessing Muslims for 7 years for attempted murder”;

(ii) The Indian Express reported on March 19, 2006: “7 Muslims convicted for life for the murder of Mukesh Panchaal”;

(iii) The Indian Express reported on March 29, 2006: “9 Muslims convicted for attempted murder and Arms Act with sentences ranging from 10 years to 18 months”; and,

(iv) The Indian Express reported on May 19, 2006: “4 Muslims nailed by DNA tests and convicted for life”.

While the ‘secular’ parties and the ‘secular’ Delhi-based media singled out the Hindu backlash for mega-publicity, they blacked out the Godhra carnage as well as the Muslim counter-attack for reasons best known to them. Nevertheless, not only the minority community of Gujarat but the entire population of that State is well aware of the truth about Gujarat, or “Gujarat Ka Sach”.

Tehelka and the sponsors of Tehelka have tried to vitiate the communal harmony not only of Gujarat but also of the entire country. Tehelka ‘sting operation’ clearly attracts Section 153A of the IPC. As Tehelka, and the television channels that broadcast studio simulated images of the riots, are headquartered in Delhi, it is incumbent upon Delhi Police, and consequently the Government of India, to take legal action against them under Section 153A of the Indian Penal Code.

Courtesy: "The Pioneer"

Duty does not permit repentance —The butchers of Calcutta

-Andrew Whitehead

Gopal 'Patha' Mukherjee, Gopal the Goat, looks an unlikely retired gang leader. He is positively beatific, with his thick, black-rimmed spectacles, long white beard, and tidy wisp of grey hair tied up on top of his head, sardar-style.

Yet, half a century ago, he was among the most feared of Calcutta's musclemen, with 800 boys at his command. He was an emperor and they were his army. Gopal Patha he got the name because his family ran a meat shop on College Street was, at the time of partition, a protector of his community. His idea of keeping the peace was killing the other side.

"He was very ferocious," recalls S. K. Bhattacharjee, a sub-inspector in the Lalbazar police headquarters at the time of the Great Calcutta Killing in August 1946. **"Gopal Patha looked like a gentleman. He was a criminal, but he was very helpful to the poor. During the riots, he came out to rescue Hindus."** Then as now, gang leaders needed political patrons, and politicians were keen to have friends in low places. Gopal Patha, sitting in his office near Calcutta's Wellington Square, says he was close to the Congress Chief, B. C. Roy though he insists this was a personal friendship more than a political allegiance.

Whatever the inspiration, when Direct Action Day unleashed communal rioting in Calcutta, Gopal Patha assembled his force. "It was a very critical time for the country," he asserts. "We thought if the whole area became Pakistan, there would be more torture and repression. So I called all my boys together and said it was time to retaliate. If you come to know that one murder has taken place, you commit 10 murders. That was the order to my boys."

The words are uttered so softly, it takes a while for their import to sink in. Calcutta was in flames and Gopal Patha, in effect, took the opportunity to douse the city in kerosene. "It was basically duty," he insists. "I had to help those in distress."

Today, his modest office is grandly titled the National Relief Centre for Destitutes. Apparently, a charity clinic occasionally operates from there. On the walls are black-and-white portraits of a pantheon of Bengali heroes, the garlands greying with dust and decay. And behind the door, sufficiently lifelike to unnerve the unwary, is a life-size model of Netaji, dressed in INA uniform, right down to the spit-and-polish military boots.

"People used all sorts of weapons," says Gopal Patha, relishing the opportunity to reminisce. "They had small knives, big choppers, sticks, rods, guns, and pistols. I had two American pistols. We got some weapons during the 1942 movement. Then during the Second World War, the American army, the Negroes, were in Calcutta. If you gave them Rs 250 or a bottle of whiskey, they would give you a pistol and a hundred cartridges. That way we secured all these weapons, and we used them during the troubles."

He made plenty of enemies. "We came to know a Hindu called Gopal Patha," recalls former Muslim Leaguer G. G. Ajmiri. "He used to catch hold of Muslims and slaughter them." Ajmiri was a Muslim strongman, a leader of the League's student wing in Calcutta along with Mujibur Rahman ("He was not that important then.") and a member of the Muslim National Guard.

Ajmiri, who appears to have been loyal in turn to Britain, to Pakistan (he served in its army) and now to Bangladesh, lives in Dhaka, where he delights in telling tales of his prowess. "They used to call me 'brave'; 'strongarm'. I never used a shotgun or sword. But I was a good boxer. And sometimes I took the bamboo sticks out of their hands and beat them with those."

"One day," says Ajmiri, warming to his theme, "somebody said: Gopal Patha has grabbed four Muslims and slaughtered them. Immediately, we rushed there. Gopal Patha looked at me and said: 'Oh, this man has come again.' So I said, 'Yes. Why are you killing people just because they are Muslims?' He said to me: 'You go, we won't kill anybody now.'"

Patha ripostes that his boys were always selective. “We fought and killed our attackers. But why should we kill an ordinary rickshaw-wallah or hawker?” For every first division gang leader like Gopal the Goat, there was a cluster of lesser figures, people like Jugal Chandra Ghosh, also now in his eighties. Still a big bear of a man, he was in 1946 a worker with the Congress Party’s trade union wing. But that wasn’t the source of his street power.

“I had a club, *an akhara*,” he says. “I was a wrestler, and I trained my boys, and they carried out my instructions. There was this Congress party leader. He took me round Calcutta in his jeep. I saw many dead bodies, Hindu dead bodies. I told him: ‘Yes, there will be retaliation.’”

“I went round the saw mills and factories. I set an amount sometimes Rs 1,000, sometimes Rs 5,000. They paid up. Then I declared: for one murder, you get Rs 10, for a half-murder, Rs 5. That’s how we got started.”

A year after the Killing, Gandhi came to a still-smouldering city and appealed for a surrender of arms. The journalist Sainen Chatterjee witnessed the scene. “People came with their weapons and placed them at the feet of Gandhiji. Shabbily-dressed people came with swords, daggers and country-made guns. Even Mountbatten said this was the miracle of Calcutta. Gandhi’s miracle.”

Ghosh was among those who surrendered their arms. It was a remarkable conversion, and Ghosh remains a committed Gandhian. In the aftermath of Ayodhya, he worked hard to prevent communal unrest in his mixed area of Calcutta. But there were limits to the miracle. Some strongmen, those who had fanned the flames so diligently over the previous year, took an intransigent line. **“Gandhi called me twice,” Gopal Patha says. “I didn’t go. The third time, some local Congress leaders told me that I should at least deposit some of my arms.”**

“I went there. I saw people coming and depositing weapons which were of no use to anyone out-of-order pistols, that sort of thing. Then Gandhi’s secretary said to me: ‘Gopal, why don’t you surrender your arms to Gandhiji?’ I replied, ‘With these arms I saved the women of my area, I saved the people. I will not surrender them’”.

With a steely glint in his eye, the sort which distinguishes the goonda from the loudmouth muscleman, Gopal Patha continued: **“Where was Gandhiji, I said, during the Great Calcutta Killing? Where was he then? Even if I’ve used a nail to kill someone, I won’t surrender even that nail.”** His sober determination underlines one of the tragedies of Partition fifty years on, so many of those who killed still have no sense of regret.

Also part of BBC Radio series on partition by Whitehead.

Courtesy: "The Indian Express" July 1, 1997, p. 8

Am I a Hindu?

-Chandan Mitra

A London datelined report last week said that a school run by a Hindu religious foundation had laid the criteria to qualify as a “practising Hindu”. Only those who fulfilled these would be considered for 30 generous scholarships offered by the Avanti Krishna School in Harrow on London’s outskirts.

Apparently, under British Government rules, educational institutions run by religious foundations can receive official funding only if they prove that special benefits are extended to members of the community they purportedly cater to. That requires such institutions to classify the defining characteristics of the religious group concerned. This poses no problem for “people of the Book” — Christians, Muslims, Jews and most major religions. But, in order to qualify for Government assistance Hindu institutions, too, had to define “Hindu”.

The neo-Hindu foundation, apparently linked to the Krishna Consciousness movement, faced a dilemma. There is, after all, no authoritative definition of what makes a person a Hindu. For more than 5,000 years that Hinduism has flourished in the geographical confines of the Indian subcontinent, nobody has attempted this mind-boggling task. However, in their eagerness to attract funding, the school authorities hurriedly put down a definition conforming, predictably, to their own beliefs and practices.

According to the conditions laid down, to be a “practising Hindu” a person had to: (a) Offer prayers daily at a temple or in the home; (b) Participate in temple activities/rituals at least once a week; (c) Perform voluntary services in a temple at least once a week; (d) Follow the tenets of Hindu scriptures, particularly the Bhagavad-Gita in everyday life; and (e) Abstain from consumption of meat, alcohol and tobacco as a matter of principle.

As the report unravelled, I shuddered. By this definition, I do not qualify to be a Hindu at all. In fact, I don’t fulfil a single criterion. While I do occasionally offer prayers at home, I do not visit temples regularly. Of course, I have gone to Tirupati, Varanasi, Kalighat and some other Hindu shrines, but except on Saraswati Puja (Vasant Panchami)

I do not usually pay obeisance at temples unless I get an urge. On occasions such as launching a new project or entering a new home, I do organise a puja and devoutly offer prayers while, conversely, avoiding starting anything new on inauspicious periods such as pitrapaksh. Diwali is observed at home and office every year, but that is about all by way of participation in rituals. I have read and tried to comprehend the Bhagavad-Gita and some Upanishads, but have never consciously thought of following the tenets of the Gita in everyday life, whatever that means. And as for abstinence from meat, alcohol and smoking, I am “guilty” on all three counts. So am I a Hindu?

But then, I have always prided myself for being a Hindu, though I am probably more of a “political Hindu” than a religious one. Till the Harrow school chose to define Hinduism in a narrow, sectarian way I never thought it necessary to conform to a rigid set of doctrines to belong to my own faith. Perhaps, it is not the fault of the foundation. Seeking Government funding is a legitimate pursuit of any social or educational institution.

Here the Central Government subsidises Haj pilgrimage while some State Governments, almost in retaliation, nowadays offer financial packages to pilgrims undertaking the arduous trek to Kailash-Mansarovar. Land is given at subsidised rates to charitable institutions, most of which are run by religious bodies. So, the Avanti Krishna School at Harrow cannot be faulted for seeking official funds. The problem lies with British rules and procedures, which are based on the underlying assumption that religious identities are codified in accordance to scriptures. This is axiomatic for Judeo-Christian (or Abrahamic) faiths, which originated in the same geographical area and share cultural and theological commonalities. Incidentally, most Indic religions too are clearly demarcated. There is no difficulty about defining a Jain, Buddhist or Sikh (although there are some

breakaway sects there too), even if these religions share an entire body of philosophy with Hinduism. But try defining a “practicing” Hindu and you open a Pandora’s box.

At the risk of sounding like woolly-headed liberals, a tribe I intellectually despise, I have always believed that liberalism is my religion’s greatest strength. Consider the sheer diversity of beliefs and practices that are accommodated happily within its ample bosom. The Kashmiri Pandit is an avid meat/ fish eater and yet this community is regarded as one of the purest Brahmin sub-groups.

Similarly, the Namboodiris of Kerala are rather eclectic in their dietary preferences but they are traditionally ordained priests of the holiest Hindu shrines including the Pashupati Nath temple in Kathmandu. On the other hand, Tamilian Brahmins are vegetarian fundamentalists. The daughter of one of Karnataka’s leading Christian political families told me that they were once high caste Brahmins ostracised for consuming fish and, in protest, converted to Christianity. Even now, arranged marriage in that family happens only among fellow Brahmin-Christians!

The *mahant* of the Gorakh Nath *Math* in Gorakhpur is necessarily a Rajput, not qualified to priesthood under the chaturvarna classification. My own upper caste (Kayasth) claims were rubbished by a priest in Haridwar. He informed me that pandas there clubbed all castes from Bengal, Orissa and Assam together, because we consume fish and meat. Yet these States boast Kalighat, Jagannath Puri and Kamakhya, three of Hinduism’s holiest shrines.

In Delhi’s Bhairon Mandir (opposite Pragati Maidan), the standard offering is a bottle of rum, whisky or more frequently country hooch. After a few drops are poured on the lingam, the bottle is returned to the devotee as prasad! Examples of this bewildering diversity can be multiplied ad infinitum.

The time, in fact, is for greater liberalism rather than constriction. I was distressed when some Balinese Hindus were recently denied entry to the Jagannath temple in Puri because they didn’t “look like Hindus”.

Having visited Bali, 97 per cent of whose population is Hindu, thanks to the 6th Century mission of Swami Markandeya, it was shockingly insensitive of the Puri priests to do this. They obviously do not know that on Mauni Amavasya, the busy N’gurah Rai Airport at Denpasar shuts down because the island observes maun or silence.

A Thai princess was recently turfed out of the same temple because she declared herself Buddhist. Incidentally, King Bhumibol of Thailand sports the title Rama IX and engaged the scholarly PV Narasimha Rao in a three-hour discussion on Hindu philosophy and scripture during the late Prime Minister’s Bangkok visit some years ago. Hinduism survives and thrives because it is a way of life, not a codified text.

We are different from others because anybody who considers himself or herself a Hindu is a Hindu; nobody has the right to decide who is a Hindu and who isn’t. So, regardless of the firman of the ayatollahs of Harrow I remain a proud Hindu.

Courtesy: "The Pioneer"

The dragon still looms

-Udayan Namboodiri

Forty-five years ago this week, a 'Himalayan Blunder' brought about the Chinese invasion of India, which is yet to be reversed

The dragon may be mythological beast, but as a metaphor for China's menacing military might in South Asia, its fittingness can never be disputed. Forty-five years ago this week, China offered a humiliating "ceasefire" to India (on November 20, 1962), four weeks after launching what it described as a "pre-emptive offensive" all along a border that India had considered "settled". Even today, the wounds on the collective memory remain open. But we are not talking only of the past here. The future promises more ignominy.

The generation that lived through that humiliation has ripened with age, but is none the wiser as to the reasons why independent India suffered its first — and, as yet, only — military debacle. The only official inquiry that was ordered into it clammed up and the contents of its report may perhaps never be known. **To those that followed, a fear of a repeat (so overwhelming was the Chinese offensive that it is still recalled) may be unreal, but they continue to experience the vestiges of mutual distrust, thanks to the inability of Communist China to accept democratic India as an equal.**

There are hundreds of little ways in which China continues to harass India. Apart from holding on to more than 38,000 sq km of Indian territory in Jammu & Kashmir and another 5,180 sq km through an illegal deal with Pakistan, Beijing routinely slights India by refusing to widen the United Nations Security Council and vetoing her rightful place as a nuclear power.

Earlier this year, China refused an Indian official from Arunachal Pradesh a visa saying the man did not need one to enter his "own" country — a reminder of Beijing's refusal to accept the status quo ante. Official Chinese propaganda still holds that India is an expansionist power with designs on its neighbours. Directly or otherwise, China funds India's insurgents, transfers nuclear and missile knowhow to the other belligerent, Pakistan, and sets for New Delhi all kinds of diplomatic puzzles with respect to the rest of the neighbourhood.

The most tell-tale aspect of the strategic balance being in China's favour is the series of apparently innocuous military collaborations that Beijing has firmed up with India's neighbours over the past decade. This was confirmed by China itself when, in September 2007, it decided to re-enter the United Nations Arms Registry, arguably the only transparent source of obtaining information on who is selling what to whom in the international arms bazaar. The highlights of China's defence collaborations include:

The Chinese F-7 is the backbone of the Pakistani Air Force. Pakistan has also ordered for 250 new generation Chinese F-17s fitted with Russian RD-93 engines.

For Bangladesh, China is principal arms supplier. China admits to selling Bangladesh 65 large-calibre artillery systems, 16 combat aircraft and 114 missile and related equipment last year. There is evidence of Nepal having bought Chinese artillery systems over the past two years. There is another chilling, yet untold, aspect. Pakistan has emerged as a major arms seller in the region. In August 2000, Pakistan surprised the world when Gen Pervez Musharraf, then a little-known pariah in the international community, announced that the country would be exporting armaments. Soon, China's hand was apparent when it was revealed that the so-called "Pakistani" Al-Khalid tanks had been developed by China North Industries Corporation. Pilot production had started in November 2000 and by May 2002, Pakistan signed a contract with the Ukrainian Malyshev tank plant for the supply of TD-2 engines.

By 2007, Pakistan, with a little help from China, has gone deep into the metamorphosis from being a basket case insofar as military hardware is concerned to a supplier. The international community has expressed

concern at this, particularly after the role of Abdul Qadeer Khan in supplying nuclear knowhow to Iran became public knowledge. But this concern has not been translated into action.

Recently, the Greens Party of Germany pulled up the Bonn Government for circumventing the European Union Committee on Arms Exports by agreeing to sell three HDW type U-214 submarines to Pakistan. Germany also intends to supply LUNA lightweight close reconnaissance and surveillance UAV system manufactured by EMT Company. Pakistan would be acquiring 30 drones along with six vehicle-mounted Ground Control Systems and six launchers. In addition, Germany would be supplying 1,000 advance Armoured Personnel Carriers.

The world does not seem to take notice of the twin dangers posed by the Sino-Pak collaboration. First, the NATO powers and the United States are contradicting, apart from domestic codes, the very purpose of their engagement in Afghanistan by arming a country with dubious commitment to the war against terrorism with a dictator whose power is under threat from fundamentalists.

Second, Pakistan and China are both rogue powers who are out to encircle India, a country which is the repository of huge Western investments, with hostile powers.

In fact, the deals that Pakistan, obviously a proxy of China, has struck with Bangladesh have already come under a cloud for the corruption involved. The Defence Exports Division of the Pakistan Army is now trying to cover up allegations of supplying sub-standard defence hardware. Sri Lanka, to whom Pakistan sold China-origin Al-Zaraar tanks, has raised the issue with faulty air weapon fuses.

Bangladesh has complained that the ammunition for the T-69 tanks was defective. Besides, hand grenades supplied by ordnance factories in Pakistan have been found to be unusable. But whatever the grouses, it looks as if the Bangladeshi would have to pay for the lemons the Pakistanis delivered.

China has a policy of to give India's strategic community a headache. Since 1995, it has embarked on a policy to keep New Delhi on its tenterhooks by encircling the "big brother" of South Asia with its small neighbours. Beijing exploited India's policy of not arming the defence forces of these countries in the hope maintaining their domestic peace as civil war conditions are ever present in Bangladesh and are quite raging in Nepal and Sri Lanka. Security expert Bhaskar Roy calls this is "New Great Wall Strategy" aimed at creating concentric circles of small countries around India, especially in the Indian Ocean outer rim. Beijing hopes that it would be able to leverage its status as arms supplier with these countries to gain effective political control.

It is quite clear, therefore, that a new competition is in the offing in South Asia. Unless India revisits its decision to compete with China only on an economic plane, there could be no stopping China's arrogance.

Courtesy: "The Pioneer"

Pakistani First Law & Labour Minister, J.N.Mandal's Resignation Letter

A Hindu leader Shri D.N. Mandal in order to earn the tag of being more secular than even the 'holy seculars' of congress, supported the Muslim League in united Bengal during India's freedom struggle immediately before 1947. He took a mistaken view that the interest of S.C. & B.C. Hindus coincide with the predominantly ately poor Muslim peasants of Bengal, and on Marxian reading a Bengali nation can be set up on class basis.

After the creation of Pakistan he was rewarded and made the only Hindu cabinet-minister of Pakistan. With in two years he became a pathetic helpless figure as he could not do any thing to prevent the persecution of Hindus in an Islamic state. In frustration he resigned on 8th October 1950. But his 'anti Hindu and pro Muslim secularism' had already done a damage to the country which could not be undone. After 57 years, Gaurav Ghosh has dug up his resignation letter to show to the public that mistakes committed around the period of partition are being repeated and how come we are doggedly determined not to learn any lesson from the past experience?

It also proves that the commonality of economic interest proved inferior to the Islamic religious interest on which Pakistan was founded. Karl Marx may have been relevant in the West during his time but he was totally out of breath with reference to Indian society and politics.

The resignation letter is a proof that Muslim ruling classes can not be trusted to keep the agreements. History of Pakistan in both East and West Pakistan is a history of rapine and rape by the police, Army and armed groups of fanatics unleashing their frenzy over the Hindu minorities and this has been going on since the creation of Pakistan leading to their virtual decimation. One can compare the percentage of Hindu population in Pakistan in 1947 and today.

The first part of this Document has appeared in our September 2007 issuly (Vol. 8 No. 6). The concluding part of this letter is produced below :-

(16) I visited Kalashira and one or two neighboring villages on the 28th February 1950. he S.P., Khulna and some of the prominent League leaders of the district were with me. When I came to the village Kalshira, I found the place desolate and in ruins. I was told in the presence of S.P.that there were 350 homesteads in this village; of these, only three had been spared and the rest had been demolished. Country boats and heads of cattle belonging to the Namasudras had been all taken away. I reported these facts to the Chief Minister, Chief Secretary and Inspector eneral of Police of East Bengal and to you.

(17) It may be mentioned in this connection that the news of this incident was published in West Bengal Press and this created some unrest among the Hindus there. A number of sufferers of Kalshira, both men and women, homeless and destitute had also come to Calcutta an narrated the stories of their sufferings which resulted in some communal disturbances in West Bengal in the last part of January.

Causes of the February disturbance

(18) It must be noted that stories of a few incidents of communal disturbance that took place in West Bengal as a sort of repercussion of the incidents at Kalshira were published in exaggerated form in the East Bengal press. In the second week of February 1950 when the Budget Session of the East Bengal Assembly commenced, the Congress Members sought permission to move two-adjournment motion to discuss the situation created at Kalshira and Nachole. But the motions were disallowed. The Congress Member walked out of the Assembly in protest. This action of the Hindu Members of the Assembly annoyed and enraged not only the Ministers but also the Muslim leaders and officials of the Province. This was perhaps one of the principal reasons for Dacca and East Bengal riots in February 1950.

(19) It is significant that on February 10, 1950 at about 10 O'clock in the morning a woman was painted with red to show that her breast was cut off in Calcutta riot, and was taken round that East Bengal Secretariat at Dacca. Immediately, the Government servants of the Secretariat struck work and came out in procession raising slogans of revenge against the Hindus. The procession began to swell as it passed over a distance of more than a mile. It ended in a meeting at Victoria Park at about 12O'clock in the noon where violent speeches against the Hindus were delivered by several speakers, including officials. The fun of the whole show was that while the employees of the Secretariat went out in procession, the chief Secretary of the East Bengal Government was holding a conference with his West Bengal counterpart in the same building to find out ways and means to stop communal disturbances in the two Bengals.

Officials helped looters

(20) The riot started at about 1 p.m. simultaneously all over the city. Arson, looting of Hindu shops and houses and killing of Hindus, wherever they were found, commenced in full swing in all parts of the city. I got evidence even from the Muslims that arson and looting were committed even in the presence of high police officials. Jewellery shops belonging to the Hindus were looted in the presence of police officers. They not only did not attempt to stop loot, but also helped the looters with advice and direction. Unfortunately for me, I reached Dacca at 5 O'clock in the afternoon on the same day, in Feb.10,1950.To my utter dismay, I had occasion to see and know things from close quarters. What I saw and learnt from first hand information was simply staggering and heart-rending.

Background of the riot

(21) The reasons for the Dacca riot were mainly five:

(i) To punish the Hindus for the daring action of their representatives in the Assembly in their expression of protest by walking out of the Assembly when two adjournment motions on Kashira and Nachole affairs were disallowed;

(ii) Dissensions and difference between the Suhrawardy Group and the Nazimuddin in the Parliamentary Party were becoming acute;

(iii) Apprehension of launching of a movement for re-union of East and West Bengal by both Hindu and Muslim leaders made the East Bengal Ministry and the Muslim League nervous. They wanted to prevent such a move. They thought that any large scale communal riot in East Bengal was sure to produce reactions in West Bengal where Muslims might be killed. The result of such riot in both East and East Bengal, it was believed, would prevent any movement for re-union of Bengals.

(iv) Feeling of Antagonism between the Bengalee Muslim and non-Bengalee Muslim in East Bengal was gaining ground. This could only be prevented by creating hatred between Hindus and Muslims of East Bengal. The language question was also connected with it and

(v) The consequences of non-devaluation and Indo-Pakistan trade deadlock to the economy of East Bengal were being felt most acutely first in urban and rural areas and the Muslim League members and officials wanted to divert the attention of the Muslim masses from the impending economic breakdown by some sort of *jihad* against Hindus.

Staggering details - nearly 10,000 killed

(22) During my nine days' stay at Dacca , I visited most of the riot-affected areas of the city and suburbs. I visited Mirpur also under P.S.Tejgaon. The news of the killing of hundreds of innocent Hindus in trains, on railway lines between Dacca and Narayanganj, and Dacca and Chittagong gave me the rudest shock. on the second day of Dacca riot, I met the Chief Minister of east Bengal and requested him to issue immediate instructions to the District authorities to take all precautionary measures to prevent spreading of the riot in district towns and rural areas. On the 20th February 1950, I reached Barisal town and was astounded to know of the happenings in Barisal. In the District of Hindus killed. I visited almost all riot-affected areas in the District. I was simply puzzled to find the havoc wrought by the Muslim rioters even at places like Kasipur, Madhabpasha and Lakutia, which were within a radius of six miles from the District town and were connected with motorable roads. At the Madhabpasha Zaminder's house, about 200 people were killed and 40 injured. A Place, called Muladi, witnessed a dreadful hell. At Muladi Bandar alone, the number killed would total more than three hundred, as was reported to me by the local Muslims including some officers. I visited Muladi village also, where I found skeletons of dead bodies at some places. I found dogs and vultures eating corpses on the riverside. I got the information there that after the whole-scale killing of all adult males, all the young girls were distributed among the ringleaders of the miscreants. At a place told Kaibartakhali under P.S. Rajapur, 63 persons were killed. Hindu houses within a stone's throw distance from the said Thana office were looted, burnt and inmates killed. All Hindu shops of Babuganj Bazar were looted and then burnt and a large number of Hindus were killed. From detailed information received, the conservative estimate of casualties was placed at 2,500 killed in the District of Barisal alone. Total casualties of Dacca and East Bengal riot were estimated to be in the neighbourhood of 10,000 killed. I was really overwhelmed with grief. The lamentation of women and children who had lost their all including near and dear ones melted my hearts. I only asked myself. "What was coming to Pakistan in the name of Islam".

No earnest desire to implement Delhi Pact

(23) The large-scale exodus of Hindus from Bengal commenced in the latter part of March. It appeared that within a short time all the Hindus would migrate to India. Awar cry was raised in India. The situation became extremely critical. A national calamity appeared to be inevitable. The apprehended disaster, however, was avoided by the Delhi Agreement of April 8. With a view to reviving the already lost morale of the panicky Hindus, I undertook an extensive tour of East Bengal. I visited a number of places in the districts of Dacca, Barisal, Faridpur, Khulna and Jessore. I addressed dozens of largely attended meetings and asked the Hindus to take courage and not to leave their ancestral hearths and homes. I had this expectation that the East Bengal Govt. and Muslim League leaders would implement the terms of the Delhi Agreement. But with the lapse of time, I began to realise that neither the East Bengal Govt. nor the Muslim League leaders were really earnest in the matter of implementation of the Delhi Agreement. The East Bengal Govt. was not only much to set up a machinery as envisaged in the Delhi Agreement, but also was not willing to take effective steps for the purpose. A number of Hindus who returned to native village immediately after the Delhi Agreement were not given possession of their homes and lands, which were occupied in the meantime by the Muslims.

Moulana Akram Khan's incitations

(24) My suspicion about the intention of League leaders was confirmed when I read editorial comments by Moulana Akram Khan, the President of the Provincial Muslim League in the "Baisak" issue of a monthly journal called Mahammadi. In commenting on the first radio broadcast of Dr. A.M. Malik, Minister for Minority Affairs of Pakistan, from Dacca Radio Station, wherein he said, "Even Prophet Mahammed had given religious freedom to the Jews in Arabia", Moulana Akram Khan said, "Dr. Malik would have done well had he

not made any reference in his speech to the Jews of Arabia. It is true that Jews in Arabia had been given religious freedom by Prophet Mahammed; but it was the first chapter of the history. The last chapter contains the definite direction of prophet Mahammed which runs as follows :-"Drive away all the Jews out of Arabia". Even despite this editorial comment of a person who held a very high position in the political, social and spiritual life of the Muslim community, I entertained some expectation that the Nurul Amin Ministry might not be so insincere. But that expectation of mine was totally shattered when Mr. Nurul Amin selected D.N. Barari as a Minister to represent the minorities in terms of the Delhi Agreement which clearly states that to restore confidence in the mind of the minorities one of their representatives will be taken in the Ministry of East Bengal and West Bengal Govt.

Nurul Amin Govt's. insincerity

(25) In one of my public statement , I expressed the view that appointment of D.N. Barari as a Minister representing the minorities not only did not help restore any confidence, but, on the contrary, destroyed all expectations or illusion, if there was any in the minds of the minorities about the sincerity of Mr. Nurul Amin Govt. my own reaction was that Mr. Nurul Amin's Govt. was not only insincere but also wanted to defeat the principal objectives of the Delhi Agreement.again repeat that D.N. Barari does not represent anybody except himself. He was returned to the Bengal Legislative Assembly on the Congress ticket with the money and organisation of the Congress. He opposed the Scheduled Caste Federation candidates. Some time after his election, he betrayed the Congress and joined the Federation. When he was appointed a Minister he had ceased to be a member of the Federation too. I know that East Bengal Hindus agree with me that by antecedents, character and intellectual attainments Barari is not qualified to hold the position of a Minister as envisaged in the Delhi Agreement.

(26) I recommended three names to Mr. Nurul Amin for this office. One of the persons I recommended was an M.A., LL.B., Advocate, Dacca High Court. He was Minister for more than 4 years in the first Fazlul Huq Ministry in Bengal. He was chairman of the Coal Mines Stowing Board, Calcutta, for about 6 years. He was the senior Vice-President of the Scheduled Caste Federation. My second nominee was a B.A.,LL.B. He was a member of the Legislative Council for 7 years in the pre-reform regime. I would like to know what earthly reasons there might be for Mr. Nurul Amin in not selecting any of these two gentlemen and appointing instead a person whose appointment as Minister I strongly objected to for very rightly considerations. Without any fear of contradiction I can say that this action of Mr. Nurul Amin in selecting Barari as a Minister in terms of the Delhi Agreement is conclusive proof that East Bengal Govt. was neither serious nor sincere in its profession about the terms of the Delhi Agreement whose main purpose is to create such conditions as would enable the Hindus to continue to live in East Bengal with a sense of security to their life, property, honour and religion.

Govt. Plan to squeeze out Hindus

(27) I would like to reiterate in this connection my firm conviction that East Bengal Govt. is still following the well-planned policy of squeezing Hindus out of the Province. In my discussion with you on more than one occasion, I gave expression to this view of mine. I must say that this policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan too. The appointment of D.N. Barari as a Minister and the East Bengal Government's unceremonious objection to my recommendation in this regard strictly conform to name of what they call an Islamic State. Pakistan has not given the Hindus entire satisfaction and a full sense of security. They now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political, economic and social life of Pakistan may not in any way be influenced by them.

Evasiveta ctics to Shelve Joint Electorate

(28) I have failed to understand why the question of electorate has not yet been decided. It is now three years that the minority Sub-Committee has been appointed. It sat on three occasions. The question of having joint or separate electorate came up for consideration at a meeting of the Committee held in December last when all the representatives of recognised minorities in Pakistan expressed their view in support of joint Electorate with reservation of seats for backward minorities. We, on behalf of the Scheduled Castes think this matter again came up for consideration at a meeting called in August last. But without any discussion whatsoever on this point, the meeting was adjourned sine die. It is not difficult to understand what the motive is behind this kind of evasive tactics in regard to such a vital matter on the part of Pakistan's rulers.

Dfismal future for Hindus

(29) Coming now to the present condition and the future of Hindus in East Bengal as a result of the Delhi Agreement, I should say that the present condition is not only unsatisfactory but absolutely hopeless and that the future completely dark and dismal confidence of Hindus in East Bengal has not been restored in the least. The Agreement is treated as a mere scrap of paper alike by the East Bengal Government and the Muslim League.

That a pretty large number of Hindu migrants, mostly Scheduled Caste cultivators are returning to East Bengal is no indication that confidence has been restored. It only indicates that their stay and rehabilitation in West Bengal, or elsewhere in the Indian Union have not been possible. The sufferings of refugee life are compelling them to go back to their homes. Besides, many of them are going back to bring movable articles and settle or dispose of immovable properties. That no serious communal disturbance has recently taken place in East Bengal is not to be attributed to the Delhi Agreement. It could not simply continue even if there were no Agreement or Pact.

(30) It must be admitted that the Delhi Pact was not an end in itself. It was intended that such conditions would be created as might effectively help resolve so many disputes and conflict existing between India and Pakistan. But during this period of six months after the Agreement, no dispute or conflict has readily been resolved. On the contrary, communal propaganda and anti-India propaganda by Pakistan both at home and abroad are continuing in full swing. The observance of Kashmir Day by the Muslim League all over Pakistan is an eloquent proof of communal anti-India propaganda by Pakistan. The recent speech of the Governor of Punjab (Pak) saying that Pakistan needed a strong Army for the security of Indian Muslims has betrayed the real attitude of Pakistan towards India. It will only increase the tensions between the two countries.

What is happening in E.Bengal today

(31) What is to the condition in East Bengal? About fifty lakhs of Hindus have left since the partition of the country. Apart from the East Bengal riot of last February, the reasons for such a large-scale exodus of Hindus are many. The boycott by the Muslims of Hindu lawyers, medical practitioners, shopkeepers, traders and merchants has compelled Hindus to migrate to West Bengal in search of their means of livelihood. Wholesale requisition of Hindu houses even without following due process of law in many and non-payment of any rent whatsoever to the owners have compelled them to seek for Indian Shelter, Payments of rent to Hindu landlords was stopped long before. Beside, the Ansars against whom I received complaints all over are a standing menace to the safety and security of Hindus. Interference in matters of education and methods adopted by the Educational Authority for Islamisation frightened the teaching staff of Secondary Schools and Colleges out of their old familiar moorings. They have left East Bengal. As a result, most of the educational institutions ago the Educational Authority issued circular to Secondary Schools enjoining compulsory participation of teachers and student of all communities in recitation from the Holy Koran before the school work commenced, Another

circular requires Headmasters of schools to name the different blocks of the premises after 12 distinguished Muslims, such as, Jinnah, Qbal, Liaquat Ali, Nazimuddin, etc. Only very recently in an educational conference held at Dacca, the President disclosed that out of 1,500 High English Schools in East Bengal, only 500 were working. Owing to the migration of medical practitioners there is hardly any means of proper treatment of patients. Almost all the priests who used to worship the household deities at Hindu houses have left. Important places of worship have been abandoned. The result is that the Hindus of East Bengal have got now hardly any means to follow religious pursuits and perform social ceremonies like marriage where the services of a priest are essential. Artisans who made images of goddesses have also left. Muslims have replaced Hindu Presidents of Union Boards by coercive measures with the active help and connivance of the police and Circle Officers. Muslims have replaced Hindu Headmasters and Secretaries of Schools. The life of the few Hindu Govt. servants has been made extremely miserable as many of them have either been superseded by junior Muslims or dismissed without sufficient or any cause. Only very recently a Hindu Public Prosecutor of Chittagong was arbitrarily removed from service as has been made clear in a statement made by Srijukta Nellie Sengupta against whom at least no charge of anti-Muslim bias prejudice or malice can be leveled.

Hindu virtually outlawed

(32) Commission of thefts and dacoities even with murder is going on as before. Thana office seldom record half the complaints made by the Hindus. That the abduction and rape of Hindu girls have been reduced to a certain extent is due only to the fact that there is no Caste Hindu girl between the ages of 12 and 30 living in East Bengal at present. The few depressed class girls who live in rural areas with their parents are not even spared by Muslim goondas. I have received information about a number of incidents of rape of Scheduled Castes Girls by Muslims.

Full payment is seldom made by Muslim buyers for the price of jute and other agricultural commodities sold by Hindus in market places. As a matter of fact, there is no operation of law, justice or fair play in Pakistan, so far as Hindus are concerned.

Forced conversions in West Pakistan

(33) Leaving aside the question of East Pakistan, let me now refer to west Pakistan, especially Sind. The West Punjab had after partition about a lakh of Scheduled Castes people. It may be noted that a large number of them were converted to Islam. Only 4 out of a dozen Scheduled Castes girls abducted by Muslims have yet been recovered in spite of repeated petitions to the Authority. Names of those girls with names of their abductors were supplied to the government. The last reply recently given by the office-in-Charge of recovery of abducted girls said that "his function was to recover Hindu girls and stat "Achuts" (Scheduled Castes) were not Hindus". The condition of the small number of Hindus that are still living in Sind and Karachi, the capital of Pakistan, is simply deplorable. I have got a list of 363 Hindu temples and gurudwaras of Karachi and Sind (which is by no means an exhaustive list) which are still in possession of Muslims. Some of the temples have been converted into cobbler's shops, slaughterhouses and hotels. None of the Hindus has got back. Possession of their landed properties which were taken away from them without any notice and distributed amongst refugees and local Muslims. I personally know that the Custodian declared 200 to 300 Hindus non-evacuees a pretty long time ago. But up till now properties have not been restored to any one of them. Even the possession of Karachi Pinjra Pole has not been restored to the trustees, although it was declared non-evacuee property some time ago. In Karachi I had received petitions from many unfortunate fathers and husbands of abducted Hindu girls, mostly Scheduled Castes. I Drew the attention of the 2nd Provisional Government to this fact. There was little or no

effect. To my extreme regret I received information that a large number of Scheduled Castes who are still living in Sind have been forcibly converted to Islam.

Pakistan 'Accursed' for Hindus

(34) Now this being in brief the overall picture of Pakistan so far as the Hindus are concerned, I shall not be unjustified in stating that Hindus of Pakistan have to all intents and purposes been rendered “ Stateless “ in their own houses. They have no other fault than that they profess Hindu religion. Muslim League leaders that Pakistan is and shall be an Islamic State are repeatedly making declarations. Islam is being offered as the sovereign remedy for all earthly evils. In the matchless dialectics of capitalism and socialism you present the exhilarating democratic synthesis of Islamic equality and fraternity. **In that grand setting of the Shariat Muslims alone are rulers while Hindus and other minorities are jimmies who are entitled to protection at a price, and you know more than anybody else Mr. Prime Minister, what that price is. After anxious and prolonged struggle I have come to the conclusion that Pakistan is no place for Hindus to live in and that their future is darkened by the ominous shadow of conversion or IQuidation.** The bulk of the upper class Hindus and politically conscious scheduled castes have left East Bengal. Those Hindus who will continue to stay accursed promise and for that matter in Pakistan will, I am afraid, by gradual stages and in a planned manner be either converted to Islam or completely exterminated. It is really amazing that a man of your education, culture and experience should be an exponent of a doctrine fraught with so great a danger to humanity and subversive of all principles of equality and good sense. I may tell you and your fellow workers that Hindus will allow themselves, whatever the threat or temptation, to be treated as Jimmies in the land of their birth. Today they may, as indeed many of them have already done, abandon their hearths and home in sorrow but in panic. Tomorrow they strive for their rightful place in the economy of life. Who knows what is in the womb of the future? When I am convinced that my continuance in office in the Pakistan Central Government is not of any help to Hindus I should not with a clear conscience, create the false impression in the minds of the Hindus of Pakistan and peoples abroad that Hindus can live there with honour and with a sense of security in respect of their life, property and religion. This is about Hindus.

No civil liberty even for Muslims

(35) And what about the Muslims who are outside the charmed circle of the League rulers and their corrupt and inefficient bureaucracy? There is hardly anything called civil liberty in Pakistan. Witness for example, the fate of Khan Abdul Gaffar Khan then whom a more devout Muslim had not walked this earth for many years and of his gallant patriotic brother Dr. Khan Sahib. A large number of erstwhile League leaders of the Northwest and also of the Eastern belt of Pakistan are in detention without trial. Mr. Suhrawardy to whom is due in a large measure the League's triumph in Bengal is for practical purposes a Pakistan prisoner who has to move under permit and can't open his lips under orders. Mr. Fazzul Huq, that dearly loved grand old man of Bengal, who was the author of that now famous Lahore resolution, is ploughing his lonely furrow in the precincts of the Dacca High Court of Judicature, and the so called Islamic planning is as ruthless as it is complete. About the East Bengal Muslims generally, the less said the better. They were promised at Lahore of an independent State. They were promised of autonomous and sovereign units of the independent State. What have they got instead? East Bengal has been transformed into a colony of the western belt of Pakistan, although it contained a population, which is larger than that of all the units of Pakistan put together. It is a pale ineffective adjunct of Karachi doing the latter's bidding and carrying out its orders. East Bengal Muslims in their enthusiasm wanted bread and they have by the mysterious working of the Islamic state and the Shariat got stone instead from the arid deserts of Sind and the Punjab.

My own sad and bitter experience

(36) Leaving aside the overall picture of Pakistan and the callous and cruel injustice done to others, my own personal experience is no less sad, bitter and revealing. You used your position as the Prime Minister and leader of the Parliamentary Party to ask me to issue a statement, which I did on the 8th September last. You know that I was not willing to make a statement containing untruths and half-truths, which were worse those untruths. It was not possible for me to reject your request so long as I was there working as a Minister with you and under your leadership. But I can no longer afford to carry this load of false pretensions and untruth on my conscience and I have decided to offer my resignation as your Minister, which I am hereby placing in your hands and which, I hope, you will accept without delay. You are of course at liberty to dispense with that office or dispose of it in such a manner as may suit adequately and effectively the objectives of your Islamic State. 8th Oct. 1950

Yours Sincerely,

J. N. Mandal

Write to: mayerdak@yahoo.com

Copyright © 2004, Nikhil Banga Nagarik Sangha

I beg to be farce

You don't understand what this Indo-US nuclear deal is all about. But you oppose it! I too don't have a clue what it is but I support it!

Courtesy: "TOI"

Diary of Events

August 1 CBI has finally chargesheeted the controversial chief of Dera Sacha Sauda, Baba Gurmit Ram Rahim Singh, for allegedly raping two *sadhvis* (women followers) of his Sirsabased religious cult and conspiring for the murder of two persons, including a local journalist who tried to expose his 'misdeeds' through his articles. *The Times of India, New Delhi, p. 9.*

_____ Buddhist spiritual leader the Dalai Lama arrived to a thundering reception at Leh to begin his 20-day tour to the hilly region. Buddhist dominated region of Jammu and Kashmir hosts Dalai Lama every year. The Dalai Lama interacted with the leaders of religious, political and social organisations and government functionaries. *The Pioneer, New Delhi, p. 18.*

_____ The United States has asked Pakistan to hand over India's "most wanted" fugitive and international terrorist Dawood Ibrahim for his alleged links to al-Qaeda-related terrorists groups and involvement in the global heroin trade. *The Indian Express, New Delhi, p. 17.*

_____ Gujarat Governor Nawal Kishore Sharma has returned 'The Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Bill 2006' to the Gujarat Legislative Assembly for reconsideration. It may be recalled that The Gujarat Freedom of Religion Act 2003 was enacted with a view to preventing conversion of persons from one religion to another by use of force or by allurements or by any fraudulent means. Bill seeks to replace definition of 'convert' by a new definition wherein a person renouncing one denomination and adopting another denomination of the same religion is excluded from the meaning of 'convert'. Stipulating that Jains and Buddhists shall be construed as denominations of Hindu religion, Shia and Sunni of Muslim religion and Catholic and Protestant of Christian religion. *The Pioneer, New Delhi, p. 8.*

August 2 BJP spokesman Ravi Shankar Prasad said every effort should be made to file an appeal against the special court judgement in the light of Madani's acquittal. He said then Home Minister L K Advani escaped only because his flight was late. *The Pioneer, New Delhi, p. 1.*

_____ A day after Gujarat Governor Nawal Kishore Sharma returned a Bill to amend the Freedom of Religion Act, the Narendra Modi Government has decided to reactivate the dormant anti-conversion law enacted by the Assembly in 2003. "The Modi Government believes that the state has been specifically targeted by some foreign powers for religious conversions, as they convert the innocent and the poor using inducements and threats. Strong nationalistic political will is needed to counter such forces, but unfortunately the opposition Congress does not believe in preserving national identity. *The Indian Express, New Delhi, p. 3.*

_____ Both ruling L.D.F. Marxists and opposition UDF have hailed Madani release-after 9 years of imprisonment in Coimbatore Jail as an aftermath of 'Bomb attack on a gathering to be addressed by home minister L. K. Advani. 37 persons perished. Advani was saved because his flight was delayed. *The Pioneer, New Delhi, p. 4.*

August 3 Interior Minister Aftab Ahmed Khan Sherpao has informed the National Assembly that six illegally constructed mosques had been demolished in the capital during the past three years. *The Pioneer, New Delhi.*

August 8 The declassified documents from 1948 show that the British Government, through out, insisted that since India has proposed the plebiscite, now its legal argument regarding the accession by Maharaja of Jammu & Kashmir should not be considered. *The Pioneer, New Delhi.*

August 10 Modernising the *madarsa* is a contradiction in terms. *Madarsa* is essentially a religious seminary and not a school for general education. Muslim rulers dominated the Indian scene for centuries in the pre-modern era. Yet, no university worth the name came into being. *The Pioneer, New Delhi.*

_____ Controversial Bangladeshi writer Taslima Nasreen was roughed up and the organisers of her book release function were injured when workers of the Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (MIM), led by three legislators, barged into the Hyderabad Press Club hall and ransacked it. *The Pioneer, New Delhi, p. 1.*

_____ Section 498A of the IPC which entails punishment of upto three years, aims at protecting women against harassment or cruelty at the hands of spouses or their relatives. "law is being blatantly abused by unscrupulous elements. The resident and non-resident Indian (NRI) husbands are being duped, cheated, humiliated, harassed and ruthlessly exploited for immigration purposes by the so-called vanishing wives. In many cases, the husbands are blackmailed, subjected to financial extortion and are even put behind bars on false charges." *The Pioneer, New Delhi, p. 1.*

August 11 After the US Senate, the California State Legislature also plans to open its session with Hindu prayers on August 27, indicating the growing influence of the Indian-American community in the political life of the United States. *The Indian Express, New Delhi, p. 10.*

August 12 Jammu and Kashmir Police claimed to have achieved a major breakthrough by killing Jaish-e-Mohammad's (JeM) India operational in-charge, who had masterminded the 2005 attack on the Ram Mandir in Ayodhya, in a gunbattle in the heart of Jammu city. *The Indian Express, New Delhi, p. 4.*

August 13 Nearly 90,000 followers of a hard-line Muslim group packed a stadium in the Indonesian capital, calling for the creation of an Islamic state and thunderously chanting "Allah is great!". *The Hindustan Times, New Delhi, p. 26.*

_____ Guru Nanak Dev idols with Chinese characteristics have flooded the shops across Punjab's markets. The Sikh clergy has issued directions not to buy these idols and those who have bought them should respectfully immerse them in the water. *The Times of India, New Delhi, p. 15*

_____ Various organisations of Hindus here today united under the banner of the Rameswaram *Shreeramsetu Raksha Manch* and held a *dharna* at Hall Gate to protest against the proposed demolition of Ram Sethu by the central government at Rameswaram. *The Tribune, New Delhi, p. 13.*

August 14 A little-known school of scholars in south India discovered one of the founding principles of modern mathematics hundreds of years before Sir Isaac Newton, to whom the finding is currently attributed, according to a new research. Dr. George Gheverghese Joseph from The University of Manchester says the 'Kerala School' identified the 'infinite series'-one of the basic components of calculus-in about 1350. *The Pioneer, New Delhi, p. 10.*

August 21 In a clear rebuff to Left parties' claims of safeguarding the national interest, strategic analysts and diplomats say that delaying the implementation of the 123 Agreement will only benefit China and Pakistan. *The Hindustan Times, New Delhi, p. 1.*

August 22 Taking advantage of the ceasefire, Pakistan has constructed 128 bunkers along the border with India, 95 of them in the Jammu sector alone. Said Minister of state for home V Radhika Selvi, written reply in Lok Sabha. *The Times of India, New Delhi, p. 19.*

_____ An 18th century Sikh shrine in Naolakha Bazaar (Lahore) has been "taken over by a group of hooligans" and the government is "hesitating to take action" against those who have locked the Sikhs out, Daily Times reported. *The Times of India, New Delhi, p. 21.*

August 26 Few people, for instance, know that the high street and hip Sector 17 piazza was a burial ground during Harappan times. This accidental find almost 40 years ago of a Harappan habitation and cemetery led to a smallscale excavation jointly carried out by the PU, Archaeological Survey of India and department of archaeology Punjab. "This was the first time that the city was linked with the Harappan age. The skeletons discovered then are preserved in the UT's museum." *The Times of India, New Delhi, p. 20.*

August 27 In a recent development, geologists working on the ONGC-sponsored 'River Saraswati project' have noticed fresh evidence of sweet water oozing out from aquifers near the ancient temples near Kalayat in Kaithal district. Dr. A. R. Chaudhari, Reader in the Geology Department, Kurukshetra University, confirmed that the interesting phenomenon had a 'feasible' connection with Saraswati river paleo channel. *The Tribune, New Delhi, p. 7.*

_____ Scientists have found uranium in "exceptionally high concentration" in Ladakh. Samples of rocks collected revealed uranium content to be as high as 5.36 per cent compared to around 0.1 per cent or less in ores present elsewhere in the country. The uranium-bearing magmatic rocks are said to be very young-between 100 million and 25 million years old. However, uranium occurs naturally in low concentration in soil, rock and water. *The Hindustan Times, New Delhi, p. 18.*

_____ Geert Wilders, Leader of the party for freedom in Netherlands with nine seats in the parliament has made a serious suggestion that *Koran* should be banned for the holi text had passages preaching violence which had an adverse effect on the community. He wants it bannished from bookshops, homes and even mosques. This has outraged the sentiments of one million Dutch Muslims. The government had to move in quickly into damage control mode. *The Hindustan Times, New Delhi, p. 28.*

August 28 Gujarat Chief Minister Narendra Modi announced a Raksha Bandhan eve gift for the girl students by providing free travel in State transport buses for the purpose of studies from September 1. *The Pioneer, New Delhi, p. 8.*

August 29 Leader of the Opposition L K Advani's efforts to amend his party's strident posturing on the Indo-US nuclear deal has found support in the RSS. RSS "appreciated the stand taken by him", over the nuclear deal. *The Indian Express, New Delhi, p. 4.*

September 1 Former Atomic Energy Commission (AEC) chairman P K Iyengar said that the Hyde Act was even more severe than the NPT. "We should not be pariahs. The deal should be discussed in Parliament. In European nations, there would have been a referendum on such an important issue. For two years we have been negotiating the deal which has been a complete waste of time," he said. *The Times of India, New Delhi, p. 9.*

_____ SC tells govt: Don't damage Ram Sethu-The UPA government's prestigious Rs 2,500-crore Sethusamudram project to dredge a shipping channel between India and Sri Lanka received a setback with the SC asking the project managers not to damage Adam's Bridge or Ram Sethu in any manner though they they could continue with dredging. *The Times of India, New Delhi, p. 13.*

_____ Two local churches in London have banned a group from conducting yoga classes because the ancient practice is allegedly "un-Christian". The church ministers branded yoga as a "sham" and "un-Christian". *The Times of India, New Delhi, p. 23.*

September 5 The RSS has warned that the India-US nuke deal will lead to American supremacy over the country's strategic programme and said the country should not open any nuclear facilities for IAEA inspections. *The Pioneer, New Delhi, p. 5.*

September 7 The Bharatiya Janata Party expressed concern over the reported directive of the Government on the posting of Muslim police personnel in the Muslim-dominated areas of the country. *The Pioneer, New Delhi, p. 5.*

_____ Many residents of DLF are aggravated with Haryana Urban Development Authority (HUDA) for not allocating land to construct a temple in DLF area for various religious gathering. *The Pioneer, New Delhi, p. 2.*

September 9 After many months of dithering, China has finally agreed to meet Indian officials on the issue of trans-border rivers. The Tibetan plateau is the principal watershed in Asia and the source of 10 major rivers, including the Brahmaputra (or Yarlung Tsangpo in Tibet), the Sutlej and the Indus. About 90 % of the rivers flow into the lower riparian states of India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam. There were reports that Brahmaputra waters may be diverted to feed its arid north. *The Times of India, New Delhi, p. 13.*

September 11 Justice S N Srivastava of Allahabad High Court, who had stirred a hornet's nest earlier by ruling that Muslims are not a minority in the state, has now come out with the order that "it is the duty of every citizen of India under Article 51-A of the Constitution, irrespective of caste, creed or religion, to follow the dharma propounded by the Bhagvad Gita." *The Times of India, New Delhi, p. 9.*

_____ Months after finishing his term in office, former President APJ Abdul Kalam is has agreed to teach at the University of Delhi's Faculty of Management Studies (FMS). *The Pioneer, New Delhi, p. 3.*

_____ In an affidavit the Centre has told the court that the Ram Setu, commonly termed Adam's Bridge is a natural formation of sand over the years and there is no archaeological or historical evidence to suggest it is the mythical Ram Setu believed to be constructed by Lord Ram to enable his army to cross over to Lanka, believed to be the empire of King Ravana in the epic Ramayana. *The Pioneer, New Delhi, p. 5.*

September 12 It is the duty of every citizen of India under Article 51-A of the Constitution-irrespective of caste, creed or religion-to follow the dharma propounded by the *Bhagvad Gita* observed a high court judge. Reacting sharply to such an order, Law Minister H R Bhardwaj said that it (judgement) should be ignored as scriptures of all religions should be respected by all. Every religion has its own *dharma shastra*, so how can we say it (Gita) is for the entire nation. *The Pioneer, New Delhi, p. 1.*

September 13 Al Qaida chief Osama bin Laden is more popular in Pakistan than president Pervez Musharraf, according to a poll. Nearly three-quarters of Pakistanis also oppose unilateral US military action against Islamic Insurgents in Pakistan's tribal areas, said the poll for Terror Free Tomorrow, a US-base organisation. *The Times of India, New Delhi.*

_____ The Kerala High Court stopped the state government from conferring the prestigious Raja Ravi Varma award on painter M F Husain after PIL said that it might disturb communal peace. *The Times of India, New Delhi, p. 11.*

_____ VHP protested against the Sethusamudram project throwing traffic out of gear at as many as 18 busy crossings in the city. Police detained around 2,000 VHP activists from the worst-affected areas like Akshardham crossing, Nizamuddin bridge, Vikas Marg, ITO, Ring Road, Aurobindo Marg, Liberty Cinema, NH-2, Uttam Nagar, Nangloi and Mangolpuri. The jams started around 9 am and lasted over two hours. The ripple effect was felt in Gurgaon and Ghaziabad. Train services were also hit. *The Times of India, New Delhi, p. 1.*

_____ A 22-year-old Dutch-Iranian will launch a campaign for Muslims to have the right to renounce their faith and find support from peers, a view which has made him the victim of three physical attacks. “We have an enormous problem with apostasy in Islam. We see a lot of problems where people want to leave Islam but they can’t.” His ‘Committee for Ex-Muslims’ wants *imams* and Muslims to recognise fellow Muslims’ right to leave their faith, and to respect freedom of religion. *The Times of India, New Delhi, p. 18.*

September 15 Within an hour of Opposition leader L K Advani raising the ASI’s affidavit on the *Sethusamudram* project with the UPA government, Prime Minister Manmohan Singh instructed Law Minister H R Bharadwaj to take “immediate measures” to withdraw the objectionable paragraph in the document submitted before Supreme Court. PM expressed his anguish to PMO officials citing the fact that Ram finds mention in the Sikh holy book Guru Granth Sahib. He even singled out the relevant excerpt from the Holy Book, referring to Page 1390 where it’s mentioned that in the Treta Yuga, the power was Ram who was from the Raghuvansh dynasty. *The Indian Express, New Delhi, p. 1 & 2.*

September 18 BJP spokesperson Ravi Shankar Prasad criticised the DMK chief for being dismissive of Ram’s existence and of the likelihood of “*Ram Setu*” being man-made. “I would like to ask him if he can make a similar statement about any other faith,” Prasad said. The flare-up has led BJP to mobilise opinion along its Hindutva plank and hark back to its argument that running down majority sensitivities was integral to “secular” politics. *The Times of India, New Delhi, p. 13.*

_____ The controversial reference in the affidavit government latter said, “The Valmiki Ramayana, the Ramcharitmanas by Tulsidas and other mythological texts, which admittedly form an ancient part of Indian literature, can not be said to be historical records. *The Times of India, New Delhi, p. 13.*

September 22 A new Homeland Security Department policy, which came into force in August, made it mandatory for Sikhs to remove their turbans at US airports for security checks. The Sikh/Hindu community is upset on new regulation. *The Times of Indian, New Delhi, p. 16.*

_____ Toronto: A series of sculptures depicting Lord Ganesha in the nude will finally be removed from display at the Canadian city of Edmonton after strong protests by the local Hindu community. *The Times of India, New Delhi, p. 16.*

September 24 A temple probably part of pre-Ahom civilisation in Assam (5th and 13th century) was discovered while some residential quarters in the hospital complex cover being demolished. A half buried stone pillar reminded the demolition man Imitiazul Ali of dream that he was surrounded by serpents and a sawage like figure asked him not to demolish the stone. On digging the DC to receiver the site for further executions around the stone the remains of the temple structure came to light with a seven snake motif. A letter has been written the tea. *The Hindustan Times, New Delhi.*

September 29 New Delhi: A city court sentenced a woman to five years’ imprisonment for acting as a conduit for terrorist organisations. The woman, identified as Anjum Zamarooda, was arrested by the Delhi police from outside the Pakistan high commission here on February 6, 2003. *The Times of India, New Delhi, p. 6.*

September 30 The trade union of the CPM, third largest trade union in the country in 1989, CITU has now slipped to fifth place, according to the findings of a verification exercise undertaken by the Central Labour Commissioner. *The Indian Express, New Delhi, p. 1.*

Select Articles

Selective insomnia : Anuradha Dutt, The Pioneer, New Delhi, August 3, 2007, p. 7.

Manmohan Singh has nightmares when a Muslim is arrested abroad, but loses no sleep when Hindu ethos is under attack in the West.

UPA Minister learns from BJP-ruled state : Ravish Tiwari, The Indian Express, New Delhi, August 4, 2007, p. 2.

For the rural road works, the Rajasthan Government introduced a system of inviting public representatives along with Government officials for joint inspection of PMGSY works. Under this model, while the superintendent engineer of the concerned zone goes for a joint inspection with the local MP every six months, the executive engineer of a division goes for joint inspection with the local MLA or chairperson of intermediate panchayat every three months.

Uruguay backs J & K separatists : Sandhya Jain, New Delhi, The Pioneer, New Delhi, August 7, 2007, p. 6.

Probably Uruguay and its American mentor want a Pakistani walkover in Jammu & Kashmir to placate Muslim rage over what is happening to the community in the Gulf and the compensation for the creation of Israel, just as Israel was compensation to the Jews for European racism and religious bigotry. We are wading the same terrain again.

123 rolls back N-arms programme : Satish Chandra, The Pioneer, New Delhi, August 8, 2007, p. 7.

If and when operationalised, the India-US civil nuclear cooperation agreement will emasculate our nuclear weapons programme. Our weapons programme will face 30 per cent and 65 per cent reduction in annual accretion of weapons grade fissile materials and tritium respectively. Plus, our weapons programme will come under American scrutiny.

The writer is former Deputy National Security Adviser.

'N-deal will hit our strategic programme' : Brajesh Mishra, The Pioneer, New Delhi, August 9, 2007, p. 7.

It's not a question of agreeing or disagreeing with the 123 Agreement, says former National Security Adviser Brajesh Mishra in a candid interview to Karan Thapar, the India-US civil nuclear cooperation deal is ab *initio* faulty. Any future nuclear test, forced by security concerns, will come with a hefty price tag, he warns, unless India can carry the NSG countries with it.

Pokhran II, 1998: India has proven its nuclear ability. But any future test will be far more expensive and the Government of the day will face a dilemma-to test, or not to test.

"India retains the Sovereign right to test. But the conditions imposed through the 123 Agreement or American laws (make it clear) the US will continue to have the right of return.

Rigveda belongs to world, not just India : Ranjit Kumar Dash, The Indian Express, New Delhi, August 10, 2007, p. 10.

Not many know that the Rigveda is what can be called man's first footprint on logos. It records the first glimmers of man's cognitive engagement, as it were, with the world in the making.

No one knows for sure how the Vedas came into existence. The dates assigned to them vary greatly, between 6000 and 1250 BCE. Tradition has it that the Vedas are ever-existent (*nitya*) and of impersonal origin (*apaurusheya*)- which is to be understood as composition by seers, of anonymous antiquity, in a state of inspiration.

The Rigveda contains the seeds of the sciences and foreshadows later schools of philosophy, social ideals and economic concepts.

Nothing to do with literacy : Balbir K Punj, The Pioneer, New Delhi, August 10, 2007, p. 6.

It isn't surprising that the moment there is some judicial verdict slamming *jihadi* terror, pseudo-secularists and Muslim communalist get into an overdrive, erecting a wall of alibis to make it appear as if one whole community is being targeted and that the community in question has enough reasons to be angry. Therefore, when some leaders and their followers in the community resort to terrorism, such 'retaliation' is justified.

The latest alibi is that Muslims are being discriminated.

Madarsas can't be secular : Prafull Goradia, The Pioneer, New Delhi, August 10, 2007, p. 7.

Madarsa is essentially a religious seminary and not a school for general education. *Madarsa* is a theological college. If such a college were ideal, it would not only teach the Holy Quran, the Hadith but also *fQh*, as interpreted by the four

different schools of Sunni Islam namely, Hanifi, Maliki, Shafii and Hanbali, to be located in four different corners of the same building.

To fund the modernisation of the system would be a waste of the tax payers' money. For such religious seminaries to offer any education which could lead to the questioning of the tenets of Islam would not be possible.

As recorded by *Mishkt*, book II, chapter I, Arabic edition, the Prophet said the *ilm* or knowledge is of three kinds-the verses of the Quran, the Hadith and the lawful interpretation of both these. Any knowledge beyond these three is unnecessary.

Syed Shahabuddin wrote, in a letter to *The Pioneer* that if there was a conflict between identity and development, the Muslims would choose the former, Earlier, Maulana Abul Kalam Azad held similar views. Consistent with this indifference towards development, there was little need for modern education.

The secular silence : Barkha Dutt, The Hindustan Times, New Delhi, August 11, 2007, p. 6.

Three legislators and a sundry assortment of political workers from a right wing Muslim party force their way inside the Press Club of Hyderabad, assault Bangladeshi author Taslima Nasreen, vandalise the venue, and then defiantly refuse to apologise, because after all they were God's own warriors, or so they claim. And yet, apart from the media's cliched fallback on interviews with the usual array of "moderate" Muslims, there's no real evidence or anger or disgust.

Where are the placard waving protestors this time? What happened to the street marches, the irate editorials and then lament for creative freedom? Does our outrage choose sides this selectively?

Dilemma of an Indian Muslim : Vir Sanghvi, The Hindustan Times, New Delhi, August 12, 2007, p. 12.

The cynical exploitation of the Muslim community by its politicians surpasses anything the BJP has ever attempted. It reaffirms the stereotype of Muslims as bloodthirsty religious fanatics who care only about beating up Taslima Nasreen and not paying maintenance to their wives. And it feeds Hindu disdain.

Ulfa kills 14 Hindi-speaking migrants : Prabin Kalita, The Times of India, New Delhi, August 12, 2007, p. 7.

January 5, 2007: Ulfa kills 45 Hindi-speaking labourers at brick kilns in Tinsukia and Dibrugarh districts. January 7, 2007: The outfit kills 117 more Hindi-speaking people in Sibsagar and Dibrugarh districts. August 8, 2007: Ulfa and Karbi Longri National Liberation Front kill eight Hindi-speaking people at Aampahar village in Karbi Anglong district.

25% teachers don't teach : Chetan Chauhan, The Hindustan Times, New Delhi, August 13, 2007, p. 1.

According to a Damning UNESCO report, which states that the Indian education system is mired in corruption and teachers are the biggest players in it, has left the HRD ministry with a red face. In India, the rate of teacher absenteeism has reached 25 per cent, the global average being 20 per cent.

The above results in the wastage of 22.5 per cent of the outlay for education. Test papers can be leaked by paying anything between Rs 3,000 and Rs 8 lakh.

But the attack was Islamic! : Prafull Goradia, The Pioneer, New Delhi, August 17, 2007, p. 7.

Plenty of heat has been generated over the attack on Taslime Nasreen in Hyderabad on August 9. There is little chance of avoiding a recurrence of such incidents. Most politicians are so obsessed with appeasing Islamists that firm action is difficult to expect instead of putting the guilty men, including the MLAs, behind bars, Hyderabad Police sent Nasreen away from the city post haste as one of the three M.L.A.s declared we are Muslims first and every thing else latter.

Deafening silence : Anuradha Dutt, The Pioneer, New Delhi, August 17, 2007, p. 7.

Why 'secularists' are indifferent towards Islamist violence. Activist Teesta Setalvad, vociferous about her antipathy to communalism has not thought it fit to lend Nasreen her support. In the forefront of the campaign to nail the perpetrators of the post-Godhra violence in Gujarat, this display of Muslim fundamentalism seems not to have pained her. Her anguish clearly is reserved for victims of Hindus. A host of intellectuals, artists, writers and activists, who have publicly showed solidarity with M F Husain, notorious for his controversial portrayals of Hindu deities, have gone underground.

What BJP Rule Meant : Christophe Jaffrelot, The Times of India, New Delhi, August 21, 2007, p. 20.

For the first time in post-independence India, Hindu nationalists were in a position to rule the country between 1998 and 2004. The impact of this unQue phase has not been assessed yet. The BJP had been voted to power to make a change after decades of Congress rule and two years of the Third Front. Government did make a change a few weeks after taking over by deciding on nuclear tests. Previous Congress governments had contemplated this move, but no prime minister after Indira Gandhi had gone ahead with it. This strategic shift may remain the only irreversible innovation of the National Democratic Alliance (NDA). Certainly the Vajpayee government introduced new measures but most of them have been undone by the UPA.

Each time Hindu nationalist leaders have been in office at the Centre, the sangh parivar has, however, been under strain. In 1977-79, 'dual membership' had been a key reason for the abortion of the Janata experiment. During 1999-2004, similar issues resurfaced. On one hand, the BJP was made of *swayamsevak*s who were supposed to pay allegiance to the RSS and its agenda; on the other, they were partners in the NDA framework who did not share their Hindutva-based ideology. The RSS acknowledged what came to be known as the compulsions of coalition politics. Things changed when some of the reforms contradicted the programme of RSS and of some of its other offshoots. Economic liberalisation, for instance, was harshly criticised by staunch advocates of *swadeshi*. Such tensions need not be overemphasised though. The sangh parivar survived similar drama in the late 1970s-early 1980s. It proved then that it was truly resilient and it is showing the same kind of quality today. However, the tenure of the Vajpayee government reconfirmed the deeply ambivalent nature of this movement: it cannot win power alone, but it refuse to share power either.

Don't Get Fooled By China, Nuclear deal is the only way to counter Beijing-Islamabad axis : K Subrahmanyam, The Times of India, New Delhi, August 28, 2007, p. 16.

The nuclear agreement could lead to the waiver of the guidelines of the 45-member Nuclear Suppliers Group (NSG) and thereby liberate India from the technology apartheid to which it has been subjected to for over three decades. China was keen on imposing the Comprehensive Test Ban Treaty on India. In a breach of the Vienna Convention, China insisted that India should be included in the list of states that should sign the treaty to bring it into force when New Delhi had already refused to accede to the treaty. It was clear the China wanted to prevent India from becoming a nuclear weapons power. Understandably Chinese reaction to the Indian nuclear test in 1998 was hostile. There are reports that Chinese personnel helped Pakistan to conduct its own test and were present at the Chagai test site. Will India accept this opportunity and help the world to balance China-a neighbour posing a surrogate nuclear threat to this country-or continue to talk only of US imperialism? India can stand up to US dominance, but it cannot wish away the India specific nuclear threat emanating from a Chinese armed Pakistan.

Mr Advani's next move : Ashok Malik, The Pioneer, New Delhi, August 28, 2007, p. 7.

The BJP's new target must be the Left. It needs to consolidate State allies on the platform of anti-Communism. It needs to point out that the Left is hypocritical, willing to implement reforms in its own States but unwilling to let Governments of other parties-whether in Orissa, Maharashtra or Andhra Pradesh-do so. Mr Advani needs to tell current and prospective allies that the Left is running counter to the country's mood. He also needs to stress a vote for the Congress may just end up being a vote for the Left because, irrespective of the current turbulence, the two could well team up after an election. The future of the BJP, then, depends not just on how trenchantly it attacks the UPA Government, but how quickly it can isolate the Left.

Raj redeemed India : Prafull Goradia, The Pioneer, New Delhi, August 28, 2007, p. 7.

British rule, despite its shortcomings, had its benevolent aspects, says Prafull Goradia.

A great deal of our ancient literature had been lost or misplaced during the medieval period. The British helped us to know more of our history than we knew. For centuries Hindus, across large tracts of the country, were suppressed subjects of Muslim despotism. With the advent of the British, the Muslims also became subjects and the Hindus came to enjoy a level playing field. One result was the Renaissance.

The 'M' in CPI(M) is for Machiavelli : Rakesh Sinha, The Pioneer, New Delhi, September 1, 2007, p. 7.

The two tendencies that made the CPI(M) in its earliest years still dominate the party's outreach. The first is a sublime loyalty to China's interests above that of India. The second is the party's ability to twist and turn every rule and ethic to subjugate a coalition Government backed by itself. Now, the time has come for a denouement.

Don't hate Bush, he's India's best friend : Swaminathan S Anklesaria Aiyar, The Times of India, New Delhi, September 2, 2007, p. 24.

Much as we may disapprove of Bush's muscularity, the record shows that no other US president has ever been willing to ride roughshod over the anti-proliferation lobby, the pro-Pakistan lobby and the pro-China lobby.

Ladakh heritage figures nowhere on Jammu-Kashmir map : Neeraj Santoshi, The Indian Express, New Delhi, September 4, 2007, p. 6.

While Ladakh has some of the world's richest heritage sites, attracting tourists from across the world, it figures nowhere on the radar of the J&K Government's own Directorate of Archives, Archaeology and Museums. "It is strange that despite Ladakh having such a rich heritage with its monasteries, sculptures, thanikas, wall paintings and mani walls, the state government has never bothered to include any site in Ladakh in its list of protected structures.

Ram Setu-BJP accuses govt of blasphemy, 'Cong playing politics of Appeasement' : Times News Network, The Times of India, New Delhi, September 13, 2007, p. 15.

Opposition BJP blasted the Congress-led UPA government accusing it of "blasphemy" for telling the Supreme Court that there was no historical evidence to establish the existence of Lord Rama or the other characters in Ramayana. BJP spokesperson Ravishankar Prasad attacked the government's stance, calling it a classic example of the politics of appeasement. "If is an insult to our cultural heritage and Hindu sentiments". Doubts were being expressed on whether the contents of the affidavit had been politically vetted. The government, which wants to demolish a part of the purported Ram Setu to dredge an 83-km-long canal linking Palk Bay and Gulf of Mannar, argues that the bridge is not a manmade structure, but a natural formation.

There was no Ram, no Ramayana : Govt, Metronow, New Delhi, September 13, 2007, p. 14.

In its desperate bid to push the *Sethusamudram* project off the TN coast, the UPA maybe just committing a historical blunder by reviving the Ram agenda for BJP.

What the Centre did was tell the Supreme Court there was no historical evidence to establish the existence of Lord Ram or the other characters in Ramayana. In an affidavit filed before the Supreme Court, the Archaeological Survey of India (ASI) rejected the claim of the existence of the "Ram Setu bridge" in the area where the project was under construction. It is asked is the statement scientific truth or political gimmick?

150-year dream for 150-year old ships : Swaminathan S Anklesaria Aiyar, The Times of India, New Delhi, September 23, 2007.

The Suez and Panama Canals save ships thousands of miles, making them profitable Sethusamundaram is not remotely comparable. It's designed for small ships. The Suez and Panama were dug through land corridors that did not face sand inundation from the sea. But Sethusamundaram will be furrow in the sea-bed, at the constant mercy of currents bearing sand.

Tibetans fear further marginalisation : Anita Katyal, The Tribune, New Delhi, September 25, 2007.

Ask any Tibetan about how the new train will change their lives and the spontaneous response is: "More Chinese". Tibetans are worried the train will only facilitate the movement of more outsiders (read Chinese) into Tibet who are better educated and will, therefore, end up grabbing the bulk of jobs.

Book Reviews

Amit Barua : Dateline Islamabad, Penguin, Rs. 295/-

Amit Barua of *The Hindu* was one of the two Indian correspondents who was allowed to report from Pakistan towards the end of the 20th century. *Dateline Islamabad* is his account of those tumultuous years-between 1997 and 2000.

An assignment in Pakistan for an Indian newsperson has never been a bed of roses. Barua was looked upon with suspicion by his Pakistani counterparts and faced open hostility from the Government. His socialising was restricted to the Indian coterie and his visits outside Islamabad were confined to Lahore and Karachi. Worse, he was under ISI's constant surveillance: even when he went jogging. Nonetheless, as Barua reported with appreciable finesse.

Pakistan was conceived in hate and fear-hate for Hindus and fear of being overpowered by them-and these two elements have continued to influence its behaviours since then. It has developed an obsession for, Jammu & Kashmir,

which had neither figured in the country's partition plan nor was committed to Pakistan in any manner. yet, it has fought four wars on the issue, losing every time and its foreign policy remaining largely Kashmir-centric.

Barua's narration of Pakistan's internal situation is superb, as has been his account of the climactic tussle between Nawaz Sharif and Gen Musharraf.

-Sanjoy Bagchi Courtesy-The Pioneer, New Delhi

Julian Crandall-Hollick : Ganga, Random House, Rs 450/

Ganga is dying. The river which has provided 'salvation' to millions of believers is left choking due to human as well as industrial pollutants. Even the World Wide Fund for Nature reached the same dreary conclusion when it placed Ganga in the list of 'World's Top 10 River at Risk' of drying up. Yet, no alarm rang in the country-symptomatic of what Arab traveller Alberuni once termed "fatalistic resignation" of Hindus, for whom the river is a living embodiment of both mother and goddess. Julian Grandall Hollick's *Ganga* deals precisely with this paradox: How can Indians pollute Ganga yet worship it as a goddess? But the paradox of Hindu indifference toward Ganga still remains unanswered. It is this fatalistic religiosity which makes us so indifferent towards the fate of Ganga. Hollick puts up a big question: "Ganga is in danger of dying-if the river dies, will the goddess die too?" Only the time will give the answer. But if we continue to remain indifferent to the disaster, we might end up losing both the river and the goddess.

-Utpal Kuma Courtesy-The Pioneer, New Delhi

Krishnan Ramaswamy, Antonio de Nicolas & Aditi Banerji (Edited) : Invading the Sacred: An analysis of Hinduism studies in America, Rupa, Rs. 595/-

Indology remains rooted in its colonial past. During its brief existence, Indology has rested on two pillars-the Aryan invasion/migration myth and the Hindu religion. Six decades after the collapse of Nazi Germany, the myth is now in its last gasp, despite a last ditch effort by a few fringe groups to keep it alive in the guise of Indo-European studies and philology.

One of the contributors (Balagangadnar) makes the perceptive observation that the social sciences and the humanities in the West are rooted in Christian theology. And for this reason, in rhetoric and conclusions, these scholars are often indistinguishable from Christian missionaries of a hundred years ago.

The book seeks to analyse the causes and effects of academic Hinduphobia in the US.

-N.S. Rajaram Courtesy-The Pioneer, New Delhi

Rachel Dwyer : Filming the Gods, Routledge, Rs. 350/-

Indian cinema is probably the most analysed, dissected and diagonised aspect of the country's values and culture. Rachel Dwyer, the author of this excellent work, refers to some three hundred odd books and articles on the subject which shows the great interest evinced by scholars in Indian cinema as a means of communication, cutting across religion, language and other forms of societal identification.

More than the media, cinema has had an outreach that defies imagination. Whether it is Raj Kapoor or Amitabh Bachchan, Lata Mangeshkar or Mukesh, they have reached every corner of India by their acting and singing and are known and admired names. And may it be remembered, long before even the print media came into existence, music and dance were the hallmark of Indian culture, though their outreach was limited and largely confined to elite audiences, like a Maharaja's *darbar*.

Indian cinema showcased the country's composite and seldom recognised culture, writes M V Kamath.

-M V Kamath Courtesy-The Pioneer, New Delhi

सांस्कृतिक गौरव संस्थान के प्रकाशन

नस्तक का नाम	मूल्य		
1. विश्वव्यापी भारतीय संस्कृति	95.00	लेखक : श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा	
2. स्मृतियों में भारतीय जीवन प)ति	90.00	लेखक : श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा	
3. इस्लाम के सैनिक	20.00	लेखक : श्री ऋषोत्तम	
4. मुस्लिम राजनीतिक चिंतन और आकांक्षाएं	20.00	लेखक : श्री ऋषोत्तम	
5. भारत में मुस्लिम जनसंख्या का विस्फोट	15.00	लेखक श्री बलजीत राय	
6. तालिबान इस्लाम और शान्ति	20.00		
7. भारत में पाकिस्तान की आइ.एस.आई.	15.00		
की घातक गतिविधियां		लेखक : कर्नल श्याम कुमार	
8. अयोध्या विवाद का हल	20.00	लेखक : डॉ. सुरेन्द्र	
9. श्रीराम जन्म भूमि सच जानिए !	140.00		
10. हमारे मूल कर्तव्य	80.00	लेखक : डॉ. विजय नारायण मणि त्रिपाठी	
11. भारतीय जीवन मूल्य	200.00	लेखिका : डॉ. कामिनी कामायिनी	
12. आज इस्लाम के मसले	65.00	लेखिका : सुश्री इशार्द मांझी (कनाडा)	
		भाषांतरकार : मे. ज. (से. नि.) वि. जोगलेकर	
13. भारत में सेक्युलर राजनीति	55.00		
14. The Nefarious Activities of Pak's I.S.I.	15.00		
		लेखक : कर्नल श्याम कुमार	
15. The Challenge of Truth - Through answers to some F.A.Q.	120.00		
16. FACT - Focussed Awareness & Complete Truth बड़ा आकार (सचित्र)	500.00		
17. The Ayodhya Controversy	20.00	लेखक : डॉ. सुरेन्द्र	
18. Minorities and Social Justice: Problems & Policy Options	20.00		
		Sh. B.P. Singhal	
19. The Glory that is Hindutva	10.00	Sh. B.P. Singhal	